A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 23 फरवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 143, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' से भारत को क्या हासिल हुआ?

उमंग पोद्दार

पाँच दिन, 20 देशों के प्रमुख, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के बीच बातचीत, और दिल्ली के बीचों-बीच लाखों लोगों का जमावड़ा। इस दौरान हर जगह दो शब्द सुनाई देते रहेः आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस।

भारत सरकार के मुताबिक़, 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट था। ब्रिटेन, साउथ कोरिया और फ्रांस में ये समिट होने के बाद, पहली बार 'ग्लोबल साउथ' के किसी देश में ये समिट हुई।

21 फ़रवरी को 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इस डिक्लेरेशन में किए गए सारे कमिटमेंट स्वैच्छिक हैं, यानी ये उन देशों की इच्छा पर निर्भर है कि वे इसके मुताबिक़ कितना काम करते हैं।

इस डिक्लेरेशन में देशों ने इस समिट में सात चक्र में हुई चर्चाओं का संज्ञान लिया और कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में हुए एआई समिट से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के विकास में अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान भी किया जाएगा। समिट में चर्चाएं सात स्तंभ, या चक्रों पर आधारित थीं। इनमें शामिल थे- एआई के संसाधनों को डेमोक्रेटाइज़ करना यानी उसे लोगों तक पहुंचाना, एआई को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनाना, इत्यादि। अब तक के एआई समिट में दिल्ली डिक्लेरेशन का समर्थन सबसे अधिक देशों ने किया है। 20 फ़रवरी को भारत और अमेरिका के बीच 'पैक्स सिलिका' का समझौता हुआ। 'पैक्स सिलिका' अमेरिका का शुरू किया हुआ वह समझौता है जो देशों के बीच आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है।

अभी तक आठ देश इस समझौते पर दस्तख़त कर चुके हैं, जिनमें जापान और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं।

'पैक्स सिलिका' पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने शुरू किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे चीन की बढ़ती ताक़त को रोकने लेने के लिए बनाया गया था। इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये समझौता भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में बढ़ोतरी लेकर आएगा।

19 फ़रवरी को अश्विनी वैष्णव ने 'न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स' की घोषणा की। इसके तहत विदेशी और भारतीय कंपनियों ने कुछ वोलंटरी या स्वैच्छिक, वादे किए। इसके दो मुख्य पहलू हैं. पहला कि डेटा के माध्यम से ये विश्लेषण करना कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रोज़गार और अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क़ पड़ रहा है। दूसरा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों में लेकर आना। इस समझौते को अपनाने वाली कंपनियों में ओपनएआई, गूगल और एंथ्रॉपिक जैसी विदेशी कंपनियों और सर्वम, ज्ञानी एआई जैसी भारतीय कम्पनियाँ शामिल हैं। हालांकि, इस स्वैच्छिक समझौते से क्या ज़मीनी बदलाव आएगा, यह बता पाना मुश्किल है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बच्चों की सुरक्षा पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े क़दम उठा चुका है। साथ ही, उन्होंने ये इशारा किया कि भारत भी उन देशों की सूची में शामिल होगा जो बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इमैनुएल मैक्रों के तुरंत बाद भाषण देने गए थे, उन्होंने भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात नहीं कही है। लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है।

वहीं एआई समिट के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत कर रहा है कि उम्र के हिसाब से एआई के इस्तेमाल पर कोई रोक लगाने की ज़रूरत है या नहीं। समिट के दौरान भारत के तीन एआई मॉडल को भी लॉन्च किया गया। इन तीन मॉडल के नाम हैं- सर्वम, ज्ञानी और भारतजेन। इन मॉडल्स का फ़ोकस भारत की भाषाओं के इस्तेमाल पर था। साथ ही, समिट के दौरान कई कंपनियों ने भारत में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में निवेश करने के वादे भी किए। इसमें रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कई कंपनियाँ शामिल हैं।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कई विवादों में भी घिरा रहा। इनमें सबसे चर्चा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर चीन से लाया गया एक 'रोबोट डॉग' था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफ़ेसर ने इस 'रोबोट डॉग' के बारे में कहा था कि उसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया, जबकि असल में वो चीन से ख़रीदा हुआ था। इसके बाद इस मामले पर बड़ा विवाद हुआ, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल ख़ाली कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने इस विवाद पर सफ़ाई भी दी।

इसके अलावा, समिट में भाग लेने वाले कई लोगों की शिकायत थी कि समिट के दौरान कई तरह की अव्यवस्था थी। सिक्योरिटी चेक के लिए लंबी क़तारें, वीआईपी मूवमेंट के लिए सड़कें ब्लॉक कर दी गई थीं, जिसकी पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि, ये शिकायतें पहले दिन सबसे ज़्यादा थीं। आगे के दिनों में लोगों का कहना था कि आने-जाने, खाने इत्यादि की व्यवस्था में सुधार हुआ, और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

समिट के दूसरे दिन, यानी 17 फ़रवरी को, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किसी को समिट में दिक्कतें हुई हैं तो वो इसके लिए माफ़ी माँगते हैं और कहा कि समिट का आयोजन बेहतर करने में जुटे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी-शर्ट उतारकर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया था। कई विशेषज्ञों ने समिट की आलोचना भी की. टेक पॉलिसी विशेषज्ञ अपार गुप्ता ने अपने एक लेख में लिखा कि 'इस इवेंट का एजेंडा था एआई को लोगों तक पहुंचाना। हालांकि, इसमें सरकार और बड़ी टेक कंपनियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। वहीं, ह्यूमन राइट्स और उन पर काम करने वाली सिविल सोसाइटी संस्थानों की भागीदारी कम थी।'

साथ ही, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी भी पुरुषों के वर्चस्व का स्पेस है। महिलाओं की क़तारें समिट में पुरुषों के मुक़ाबले काफ़ी छोटी थीं। साथ ही, ज़्यादातर कंपनी के सीईओ और स्टॉल्स पर पुरुष ही लोगों को समझाते और अपने प्रोडक्ट्स या कंपनी के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे थे।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

एआई समिट को कांग्रेस ने बनाया नंगी राजनीति का अखाड़ा

शर्टलेस प्रदर्शन पर पीएम मोदी का रिएक्शन,जमकर लगाई लताड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन को कांग्रेस की गंदी राजनीति का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। रविवार को मेरठ में अपने संबोधन के दौरान कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन देश में ही कुछ राजनैतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। पूरा देश गर्व से भर गया लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया। कांग्रेस ने गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।

समाजवादी पार्टी पर भी बरसे पीएम मोदी

समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तब यह सब संभव ही नहीं था क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं घोटालों में ही गुम हो जाती थी। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर तकनीक भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया।

देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे कांग्रेसी नेता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है, ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से इन्हें कोई परहेज नहीं है, उन्हें बीजेपी, एनडीए से विरोध है लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट यह बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। यह देश का, देश के सम्मान का कार्यक्रम था लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति-नीति पर थू-थू हो रही है लेकिन दुर्भाग्य देखिए इतनी पुरानी पार्टी के नेता लजाने की बजाय गाजते हैं। देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, 2014 से पहले मेट्रो का विस्तार धीमी गति से हो रहा था।

अब 55 मिनट में दिल्ली से पहुंचे मेरठ

- पीएम मोदी ने दिखाई 'नमो भारत रैपिड रेल' के फुल स्ट्रेच को हरी झंडी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के फुल स्ट्रेच और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर का सफर अब महज 55 मिनट में पूरा होगा। इसे भारत की सबसे तेज सेमी-हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद उसमें सफर भी किया। इस

दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों से बातचीत की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, नमो भारत रैपिड रेल के संचालन में महिला सशक्तिकरण को खास प्राथमिकता दी जा रही है। करीब 80 प्रतिशत ट्रेन ऑपरेटर महिलाएं होंगी। दिल्ली से मेरठ तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि वे अब केवल 55 मिनट में यह दूरी तय कर सकेंगे। साथ ही स्मार्ट टिकटिंग वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं और क्यूआर कोड आधारित टिकट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस रूट पर कुल छह प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ताकि भविष्य में दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल रैपिड रेल को जोड़ा जा सके। हालांकि देश में अभी बुलेट ट्रेन पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नमो भारत ट्रेन में कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो बुलेट ट्रेन जैसी हैं। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।

शरद की सुबह

भीतर
बोलता है कोई
बाहर सुनता हूँ मैं

भाषा बाहर है
भीतर है भाव

भीतर लिखता है कोई
बाहर बांचता हूँ मैं

भीतर गाता है कोई
बाहर नाचता हूँ मैं

सच तो यह है कि
बाहर रहता हूँ मैं
मगर भीतर बसता है गाँव

पेड़ के भीतर
जितनी गहरी उतरती है धूप
उतनी ही बाहर
गहराती है छाँव।

- गोविन्द गुंजन

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव-2026 नॉट आउट @100 का किया शुभारंभ

मध्यप्रदेश उभर रहा है दिव्यांगजन के खेलों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश दिव्यांगजन के खेलों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाज सुधारक और चिंतक स्व. कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर 100 घंटे लगातार क्रिकेट खेलने का यह प्रयास केवल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब संकल्प समाज के उत्थान के लिए होता है तो सीमाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द को स्थापित किया है। उनका यह कदम भारतीय संस्कृति के मनोभाव के अनुरूप है। इस पहल ने विकलांग शब्द से जन सामान्य में उपजती हीनता की भावना का अंत किया है, साथ ही चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में संघर्ष की अदम्य इच्छा शक्ति को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सकारात्मक सोच के अनुरूप देश को सभी क्षेत्रों में आगे लाने के प्रयास को साकार रूप देने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट@100 का आयोजन किया गया है। मुख्मयंत्री डॉ. यादव

राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन स्टेडियम में दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांग खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिकेट पिच पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा एक बॉल खेलकर मैच का शुभारंभ किया। पहला मैच मध्यप्रदेश और राजस्थान की ऑर्थो केटेगरी टीम के बीच रहा। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव को खेल महोत्सव का बैच लगाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टूर्नामेंट की कैप भी धारण की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांग खेल महोत्सव के अंतर्गत दिव्यांगजन का लगातार 100 घंटे क्रिकेट खेलना अद्भुत, आनंददायी और हम सबके लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने इस आयोजन के लिए कुशाभाऊ ठाकरे न्यास और इंटर नेशनल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मन की बात के श्रवण के साथ यह खेल महोत्सव आयोजित हो रहा है। यह सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से समान भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांग बेटी संगीता विश्नोई की इच्छाशक्ति की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां केवल खिलाड़ी नहीं, आत्मविश्वास और साहस की जीवंत मिसाल हैं।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि विश्व में पहली बार एक ऐसा आयोजन हो रहा है जहां खेल की गूंज लगातार 100 घंटे तक रहेगी। दिन हो या रात दिव्यांग खिलाड़ी अपने प्रयासों से एक नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन खेल महोत्सव में 25 टीमों के 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह महोत्सव 26 फरवरी तक जारी रहेगा। स्थानीय विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने सभी का आभार माना। कार्यक्रम में श्री अजय जामवाल, श्री राहुल कोठारी, श्री रविन्द्र यति और दिव्यांग खिलाड़ी उपस्थित रहे।

- घाटी के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी

मुठभेड़ में 2 जैश आतंकवादी ढेर

किश्तवाड़ (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। रविवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। अधिकारियों ने बताया कि दो संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सेना के जवानों ने चतरू के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बल को घिरे हुए क्षेत्र में भेज दिया गया है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। बर्फ से ढके चतरू वन क्षेत्र में पिछले महीने आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग आधा दर्जन गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक सैनिक बलिदान हुआ और एक आतंकवादी मारा गया था।

व्हाइटनाइट कोर के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर संयुक्त अभियान में किश्तवार के पासेरकुट इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ की। गोलीबारी जारी है। सैनिकों ने इलाके को घेर लिया है,बयान में ऐसा कहा गया है।

तमिलनाडु-बंगाल से एक बांग्लादेशी समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार

हमले की साजिश थी, आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से कनेक्शन

तिरुप्पुर/नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने रविवार को 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए। पुलिस के मुताबिक यह सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। इनके पास से 12 से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुप्पुर से जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद

लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट की थीं। 3 आरोपियों को उथुकुली, 3 को पल्लादम और एक आरोपी तिरुमुरुगनपोंडी से पकड़ा गया। ये सभी फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर तिरुप्पुर में गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तमिलनाडु से गिरफ्तार 6 संदिग्धों पर आतंकियों की मदद के लिए शहरों की रेकी का आरोपी है। इसके अलावा दिल्ली में 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर लगाने में भी शामिल होने का शक है। सभी को ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है। एक दिन पहले ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर टेरर अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दिल्ली में लाल किला, चांदनी चौक में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर रख रही हैं। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 23 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

'मिनी जामताड़ा' में 34 साइबर ठग अरेस्ट, 45 आरोपी फरार

- मथुरा में 240 पुलिसवालों के साथ पहुंचे एसपी,20 गाड़ियों के पहुंचने से हड़कंप

मथुरा (एजेंसी)। मथुरा के 'मिनी जामताड़ा' में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए एक बार फिर 240 से अधिक पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की। 20 से अधिक गाड़ियों से पुलिसकर्मियों के साथ एसपी पहुंचे और दो टीमें बनाकर दो गांवों में रेड किए। पुलिस टीम को देखते ही गांव में भगदड़ मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ खेतों में छिप गए।

पुलिस ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। घरों की तलाशी ली गई। रविवार सुबह पुलिस ने विशंभरा और झंझावली गांव में रेड किए। करीब 5 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने 34 लोगों को हिरासत में लिया। एसपी सुरेश चंद्र रावत के अनुसार, पुलिस को देखने के बाद 45 लोग फरार हो गए। 5 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। दरअसल, मथुरा के बॉर्डर क्षेत्र के करीब करीब 8-10 गांव ऐसे हैं जो साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है। यहां साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क है जोकि देश-विदेशों में ठगी का अंजाम देता है।

एसआईआर में तेजी लाने ऐक्शन में कलकत्ता हाईकोर्ट

- जजों की छुट्टियां रद्द,बंगाल सरकार-ईसी में टकराव जारी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने 21 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक सभी जिला और सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इस अवधि में बिना हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति के कोई भी नई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं अभी जो न्यायाधीश अवकाश पर हैं, उन्हें भी तुरंत लौटने का आदेश दे दिया गया है। राज्य में में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण

(एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में तय किया गया कि सभी जिलों के सत्र न्यायाधीशों को एसआईआर से जुड़े दावों और आपत्तियों की दैनिक आधार पर सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, लगभग 150 सत्र न्यायाधीश इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में सात रिटायर्ड जजों के नामों पर भी प्रारंभिक स्तर पर विचार किया जाएगा, जिन्हें जिन्हें आगे के आदेशों के अधीन इस कार्य में लगाया जा सकता है।

'लौह पुरूष' की प्रभावी प्रस्तुति ने भारंगम् को नई ऊंचाई दी

शकील अख्तर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर में 25वें भारत रंग महोत्सव का समापन समारोह हुआ। इस अवसर पर पद्मश्री प्रो. राम गोपाल बजाज मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा– 'जब हमने इस उत्सव की कल्पना की थी, तब रंगमंच शून्यता और निराशा से गुजर रहा था। आज यह गुणित होकर जिस ऊँचाई पर पहुँचा है, उससे मैं प्रसन्न हूँ।'

समापन समारोह में गीतकार-गायक स्वानंद किरकिरे, वरिष्ठ अभिनेत्री मीता वशिष्ठ, गीतकार शैली, उपाध्यक्ष प्रो. भरत गुप्त और रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार मोहंती सहित अनेक विशिष्टजन उपस्थित रहे। संचालन टीवी पत्रकार वर्धन त्रिवेदी ने किया। प्रो. भरत गुप्त ने भारतीय नाट्यशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा– 'रंगकर्मी ही वह साधक है जो दिव्य को हमारे बीच अवतरित करता है।' वहीं निदेशक त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में रंगकर्म की भूमिका अहम होगी। मीता वशिष्ठ ने 'रंगदूत' के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस उत्सव ने बच्चों तक थिएटर की पहुँच बढ़ाई है और 'थियेटर स्पेस' की आवश्यकता को रेखांकित किया है। स्वानंद किरकिरे ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने 'भारंगम' को विराट और अधिक व्यापक रूप में देखा है। गीतकार शैली ने इसे रंगमंच की दिवाली जैसा उत्सव बताया और चितरंजन त्रिपाठी के परिश्रम की सराहना की। रजिस्ट्रार मोहंती ने कहा कि इस बार महोत्सव का विस्तार अभूतपूर्व रहा–देश के 41 केंद्रों और विश्व के 15 देशों तक, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी प्रदर्शन हुआ। उन्होंने सभी सहयोगियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

'लौह पुरुष' की प्रस्तुतिः समापन के बाद बहुप्रतीक्षित नाटक 'लौह पुरुष' का मंचन हुआ। एक घंटे 20 मिनट की इस प्रस्तुति में सरदार पटेल के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया। 150 कलाकारों और 20 बाल कलाकारों की टीम ने इसे जीवंत बनाया। 80×60 फीट के मंच पर सरदार पटेल की मूर्ति का उभरना और फिल्मी दृश्यों का संयोजन दर्शकों के लिये विशेष आकर्षण रहा। राजेश सिंह ने मंच सज्जा की और दूसरे चरण में सरदार पटेल की भूमिका निभाई। तकनीकी सहयोगियों और बाल कलाकारों के अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी ने प्रस्तुति को और सशक्त बनाया। भारत रंग महोत्सव में, चितरंजन त्रिपाठी के निर्देशन में यह उनकी दूसरी बड़ी प्रस्तुति रही। इससे पहले वे 'समुद्र मंथन' को महज़ एक महीने में तैयार कर पिछले महोत्सव में प्रस्तुत करने में सफल रहे थे।

'लौह पुरुष' का मंचनः समारोह में विद्यालय के रंगमंडल द्वारा नाटक 'लौह पुरुषः सरदार वल्लभभाई पटेल' का मंचन किया गया। आसिफ़ ख़ान लिखित और चितरंजन त्रिपाठी निर्देशित इस संगीतमय प्रस्तुति में संवादों की सजीवता और दृश्य संयोजन ने दर्शकों को आकर्षित कर लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शक मोबाइल पर इसके दृश्य कैद करते दिखे। नाटक के पहले निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि इसका पहला प्रदर्शन 30 नवंबर 2025 को गुजरात के केवड़िया में हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था।।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थितिः

25वें भारत रंग महोत्सव से जुड़े कुछ तथ्य

इस बार का महोत्सव न केवल प्रदर्शन बल्कि विस्तार और तकनीक के मामले में भी विशिष्ट रहा। देश के कस्बाई कलाकारों से लेकर महानगर के कलाकारों के विभिन्न शैली के नाटकों के मंचन हुए। बच्चों का रंगमंच भी आयोजन से जुड़ा। हर बार की तरह विदेशी नाटकों को भी देखने का मौका मिला। नाट्य विद्यालय के पूर्व स्नातक पकंज त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा जैसे आज के कई प्रमुख कलाकारों और निर्देशकों ने आयोजन में शिरकत की। उनके संवाद कार्यक्रम हुए।

- वैश्विक मंच पर भारतः महोत्सव में अटलांटा, कनाडा, लंदन, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, कतर, स्पेन, सूरीनाम, तंजानिया और यूएई (दुबई, अबू धाबी, शारजाह) जैसे देश शामिल हुए। इन देशों में 20 से अधिक विविध नाटकों का मंचन हुआ। स्पेन ने 'मास्क मेकिंग' पर एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की।
- अंटार्कटिका में कलाः महोत्सव का सबसे साहसिक प्रदर्शन अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा माइनस 6 डिग्री तापमान में किया गया।
- डिजिटल पहलः एनएसडी ने भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए अपना इंटरनेट रेडियो 'रंग-आकाश' और नाटकों के डिजिटल प्रसारण के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म 'नाट्यम' की शुरुआत की।
- विविधता और भाषाः 250 फुल-लेंथ थिएटर प्रोडक्शन के 280 से ज्यादा शो हुए। नागा, बृजवाली, बुंदेली, राभा, मैतेई, ताई खामती, न्यिशी, मैथिली, पुर्गी, भोटी और गारो जैसी कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं को भी मंच मिला।
- युवा और प्रयोगधर्मी रंगमंचः दिल्ली-एनसीआर के कॉलेजों द्वारा 36 स्ट्रीट प्ले, देश भर के 16 वन-एक्ट प्ले और विभिन्न भाषाओं के 33 माइक्रो ड्रामा भी इस उत्सव का हिस्सा रहे।
- विशाल भागीदारीः अकेले मंडी हाउस (ह्स्ष्ठ परिसर) में प्रतिदिन 6,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे। 'जश्ने बचपन' में 1,000 बच्चों और 'आदि रंग' में 400 आदिवासी कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
- महिला शक्ति और साहित्यः इस बार महिला निर्देशकों के 33 नाटकों का मंचन हुआ। साथ ही 19 बुक लॉन्च और चर्चा सत्र आयोजित किए गए। एनएसडी के पहले निदेशक इब्राहिम अल्काज़ी के साथ ही रतन थियम, आलोक चटर्जी, दया प्रकाश सिन्हा जैसे रंग दिग्गजों के अवदानों को याद किया गया।
- एक बड़ा परिवारः कुल मिलाकर इस 'महा-भारंगम' ने 5,000 कलाकारों, 1,000 तकनीशियनों और पर्दे के पीछे काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मियों को एक साझा मंच प्रदान किया।

विक्रमोत्सव 2026: श्रृंगार रस प्रधान चतुर्भाणी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति

डॉ. जफर महमूद

उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव के नाट्य समारोह में छटी शाम श्रृंगार रस से ओतप्रोत चतुर्भाणी पर आधारित प्रस्तुति का मंचन हुआ। चतुर्भाणी गुप्तकालीन संस्कृत साहित्य के चार प्रसिद्ध एकांकी का संग्रह है, जिसमें प्राचीन भारत के रसिक और लोक जीवन का चित्रण है। डॉ मोतीचंद द्वारा अनुवादित और डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा विवेचित इस कृति में बोलचाल की संस्कृत और नाटकीय शैली का अनूठा मिश्रण है। प्रस्तुत नाटक प्रेम,विलास,हास्य और तत्कालीन नगर जीवन की विसंगतियों को व्यंग्यात्मक रूप में दर्शाता है। इस नाटक को उज्जैन के कालिदास समारोह में प्रख्यात रंग निर्देशक बव कारंत द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन जबलपुर के राजकुमार कामले द्वारा किया गया था। चतुर्भाणी की

शुरुआत मां भारती की आराधना नृत्य-नाटिका से हुई।

महाराज शोध पीठ, संस्कृति विभाग मप्र शासन एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (भारंगम) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नाट्य समारोह में चतुर्भाणी के अंतर्गत 'उभयाभिसारिका' (वररुचि) एवं 'पद्यप्राभृतकम' (शूद्रक) पर आधारित

नाटक में कर्णीपुत्र एवं देवदत्ता के प्रेम प्रसंग को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। गलतफहमी के कारण दोनों के बीच वियोग हो जाता है। मित्र उनके पुनर्मिलन के लिए यात्रा करता है और मार्ग में विभिन्न पात्रों से संवाद करते हुए आगे बढ़ता है। वसंत ऋतु, प्रकृति सौंदर्य, मणिकाओं के जीवन और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण नाट्य में देखने को मिला। अंततः दोनों का मिलन दर्शकों के लिए भावपूर्ण क्षण बना।पद्मप्रभृतक राजा शूद्रक द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत 'भाण' एकपात्रीय नाटक है, जो 'चतुर्भाणी' का हिस्सा है। यह हास्य और श्रृंगार रस से भरपूर है, जिसमें शश नामक विट के माध्यम से मूलदेव और देवदत्ता के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें कमल के उपहार के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति का चित्रण है।

मंच पर वैशिकाचल सहित अन्य पात्रों एवं शश द्वितीय की भूमिका विक्की तिवारी ने निभाई, जबकि शश प्रथम के रूप में सिद्धार्थ श्रीवास्तव नजर आए। कर्णीपुत्र की भूमिका तरुण सिंह ठाकुर, दत्तकलशी के रूप में अश्वनी यादव, विपुलामात्य के रूप में आयुष्यमान शर्मा तथा पवित्रक एवं कवि की भूमिका साहिल ठाकुर ने निभाई। भावजरदगव एवं दर्दरक की भूमिका सत्यम प्रजापति ने सजीव की। देवसेना के रूप में राधा बर्मन और उनकी सखी के रूप में पलक तिवारी ने प्रभाव छोड़ा। नाट्य में कथक नृत्य की प्रस्तुति मुक्ति मिश्रा और हंसिका मिश्रा ने दी, वहीं लोकनृत्य में राधा बर्मन, पलक तिवारी, मुक्ति मिश्रा, हंसिका मिश्रा एवं विशाल विश्वकर्मा ने सहभागिता की। नाटक के मंचन से पूर्व नाट्य निर्देशक का सारस्वत सम्मान सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कार्य परिषद के वरिष्ठ सदस्य राजेश सिंह कुशवाह,प्रेमचंद सर्जन पीठ के निदेशक मुकेश जोशी, समाज सेवी जगदीश पांचाल तथा कमल बैरवा ने किया।

'सुप्रीम' फैसले के बाद लटक गई 'ट्रेड डील'

भारत और अमरीका के बीच नए सिरे से होगी बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगने के बाद भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित बैठक को भी नए सिरे से तय करने का फैसला किया गया है। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए वाशिंगटन में अपने मुख्य वार्ताकारों की प्रस्तावित बैठक को नए सिरे से तय करने का फैसला किया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। भारतीय दल 23 फरवरी से तीन दिन की बैठक शुरू करने वाला था। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन इस समझौते के लिए भारत के लिए मुख्य वार्ताकार हैं। एक सूत्र ने

कहा,भारत-अमेरिका व्यापार करार के लिए भारतीय वार्ताकारों की अमेरिका यात्रा के संदर्भ में दोनों पक्षों का मानना है कि अब यह बैठक तब होनी चाहिए जबकि दोनों पक्ष ताजा घटनाक्रमों और उसके प्रभाव का आंकलन कर लें। इसके लिए दोनों पक्षों को समय चाहिए।

ट्रंप के आर्थिक एजेंडा को लगा एक बड़ा झटका

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके आर्थिक एजेंडा को एक बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी शीर्ष अदालत ने उनके द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों पर लगाए गए शुल्कों को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक अधिकार कानून (आईईईपीए) का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अगस्त, 2025 में भारत पर 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया था। बाद में, रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। इससे भारत पर कुल शुल्क दर 50 प्रतिशत हो गई थी। भारत और अमेरिका इस महीने की शुरुआत में एक अंतरिम व्यापार करार को अंतिम रूप देने के लिए रूपरेखा पर सहमत हुए।

विदेशी पक्षियों से एवियारी हुआ गुलजार, उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मुकुंदपुर जू का किया निरीक्षण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मैहर जिले के मुकुंदपुर मे महाराजा मारतन्द सिंह जू देव वाईट टा इगर सफारी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनकी उपस्थिति में जू मे लाये गए विदेशी प्रजाति के पक्षी भी उनके रहास मे छोड़े गये। नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड सिगरोली द्वारा सी एस आर मद से मुकुंदपुर को प्रदाय किये गए नये विदेशी पक्षियों को वॉक इन एवियारी के अंदर प्राकृतिक निवास पर छोड़ा गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए मुकुंदपुर जू के एवीयरी मे अब नये प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी आ चुके है। जिनमें रेड स्कारलेट मैकॉ, रेड ग्रीन विंग्ड मैकॉ, सल्फर-क्रेस्टेड कॉकाटू, ब्लू गोल्ड मैकॉ, हैनस मैकॉ, अफ्रीकन ग्रे पैरोट, ग्रैंड इलेक्टस, सन कोनूर, कॉकेटियल्स, और लव बर्ड शामिल हैं। नये पक्षियों के आगमन से पर्यटक को अब और अधिक विदेशी प्रजाति के पक्षी देखने को मिलेंगे।उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने भ्रमण के दौरान पक्षियों के सरंक्षण के प्रयासो की सराहना की। इस मौके पर सीसीएफ श्री राजेश

राय, वन मंडल अधिकारी श्री विद्या भूषण मिश्रा उपस्थिति रहे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा जिले के हरिहरपुर मे की जा रही प्राकृतिक खेती का भी अवलोकन किया।

लेखक की संवेदना पाठक की संवेदना बन जाए: सूर्यकांत नागर

● हिन्दी लेखिका संघ का 31वां वार्षिक उत्सव एवं कृति सम्मान समारोह संपन्न

भोपाल। हिन्दी लेखिका संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित 31वां वार्षिक उत्सव एवं कृति पुरस्कार-सम्मान समारोह रविवार को पं. रविशंकर सभागृह, हिन्दी भवन में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आई साहित्यकारों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े ने स्वागत उद्बोधन में वर्षभर की गतिविधियों–साहित्यिक गोष्ठियों, काव्य पाठ, पुस्तक विमोचन, युवा लेखन प्रोत्साहन एवं प्रकाशन कार्यों–का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ महिला रचनाकारों को सशक्त मंच प्रदान करने हेतु निरंतर सक्रिय है। अध्यक्षीय उद्बोधन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रांतीय मंत्री डॉ. करुणा सक्सेना ने कहा, 'स्त्री जीवन संस्कार, पोषण और सृजन के साथ निरंतर आगे बढ़ता है। साहित्य केवल दर्पण नहीं, दीपक भी है। हमें केवल पीड़ा नहीं, बल्कि उसके समाधान भी लिखने होंगे।

मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यकांत

नागर (इंदौर) ने कहा, 'लेखन गंभीर साधना है। लेखन ऐसा हो कि लेखक की संवेदना पाठक की संवेदना बन जाए। प्रमुख अतिथि डॉ. संतोष चौबे, कुलाधिपति, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल एवं निदेशक, विश्वरंग ने साहित्य को वैचारिक ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि महिलाएँ पारिवारिक दायित्वों के साथ भी लेखन के माध्यम से भाषा को जीवित रखती हैं। वे भाषा में अपना ऐसा घर निर्मित करती हैं, जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता।कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित दादा कैलाश पंत जी , डॉ रामवल्लभ आचार्य , गोकुल सोनी , मुकेश वर्मा , डॉ जवाहर कर्णावत , घनश्याम मैथिल , राजेश तिवारी , मनीष बादल , डॉ संजय सक्सेना आदि साहित्यकारों की विशिष्ट उपस्थिति रही । इस अवसर पर 'सर्जना स्मारिका' का लोकार्पण किया गया। समारोह में कुसुम कुमारी जैन वरिष्ठता सम्मान श्रीमती शीला श्रीवास्तव को, डॉ. फिरोजा मुजफ्फर सेवा सम्मान डॉ. कुमकुम गुप्ता को, डॉ. सुशीला कपूर हिंदी सेवी सम्मान श्रीमती सुमन ओबेराय को तथा श्रीमती शोभा शर्मा कर्मठता सम्मान श्रीमती राधारानी चौहान को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त समग्र साहित्य, उपन्यास, ग़ज़ल, नाटक, लघुकथा, कथा, लोक साहित्य, बाल कविता, आध्यात्मिक पद्य, डायरी एवं समीक्षा सहित विभिन्न विधाओं में कृति पुरस्कार प्रदान किए गए।

मीडिया जगत सम्मान के अंतर्गत श्री मनीष गौतम, सुश्री निधि सिंह, श्री रघुवीर तिवारी, श्री सुशील पांडे एवं सुश्री अमिता त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। संघ की सचिव श्रीमती सुनीता यादव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन शशि बंसल ने तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती वर्षा चौबे ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार, बुद्धिजीवी एवं साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ऐक्शन में पुलिस

- कोर्ट का आदेश होते ही पॉक्सो में केस दर्ज, यौन शोषण का है आरोप

प्रयागराज (एजेंसी)। प्रयागराज की कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और तीन अज्ञात के खिलाफ झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में नाबालिगों के यौन शोषण और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शनिवार देर रात ही यह कार्रवाई पूरी की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस फास्ट हो गई है।

शंकराचार्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश देने के कुछ घंटे बाद ही पॉक्सो एक्ट में झूंसी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद को नामजद करते हुए नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण और धमकाने का आरोप लगाया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

विशेष न्यायाधीश दिया पॉक्सो एक्ट में केस का आदेश

प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद शनिवार को शंकराचार्य के खिलाफ केस का आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र, पीड़ित ए व पीड़ित बी के बयान, स्वतंत्र गवाहों के बयान और प्रयागराज के एडीशनल पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को ध्यान से और पूरी तरह से देखने पर यह पता चलता है कि आरोपियों पर पीड़ित ए व पीड़ित बी के साथ ही दूसरों से यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं।

इंदौर में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, कई घायल, 22 पर केस

पथराव के साथ बोतलें और टमाटर फेंके, 15 से अधिक लोग घायल

इंदौर। शनिवार दोपहर शहर के मध्य इलाके में राजनीतिक झड़प हिंसक संघर्ष में बदल गई। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के बाहर उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव होने लगा। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थरबाजी के साथ पानी की बोतलें और टमाटर फेंके जाने लगे। घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें भाजपा नेत्री बिंदू चौहान भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से पहचान कर और आरोपितों की तलाश शुरू की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया था। इस कड़ी में इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) और भाजपा कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई, जो जल्द ही पथराव में बदल गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उग्र कांग्रेसियों ने हालात को और बिगाड़ दिए। इस घटना में भाजपा नेत्री बिंदू चौहान के चेहरे पर गंभीर चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी हल्की चोटें आईं। इसके बाद आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता पंढरीनाथ थाने पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की माँग को लेकर प्रदर्शन किया।

स्थानीय निवासी दहशत में – इस झड़प को देखते हुए व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दीं और स्थानीय निवासी दहशत में आ गए। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर बल तैनात किया और देर रात शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े समेत करीब 22 नेताओं पर पुलिस ने मामले दर्ज किए। इस मामले में पंढरीनाथ पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आवेश राठौर की शिकायत पर केस दर्ज किया। इसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेडे के साथ ही अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पा मोर्चा अध्यक्ष सोना मोर्चा अध्यक्ष दौलत पटेल, सादिक खान, विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, निखिल वर्मा, महक नागर, दानिश खान, शैलू सेन, संजय बाकलीवाल, अमन बजाज, आकाश सहित 20 से अधिक पर केस दर्ज किया है।

पहले से जमा किए थे पत्थर– कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की, जबकि भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले से पत्थर और सड़े टमाटर जमा कर रखे थे और अचानक हमला किया। उनका कहना है कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उग्रता के कारण स्थिति बिगड़ गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएँगे, ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

इंदौर जिले में 24.86 लाख वोटर्स, सबसे ज्यादा 3.52 लाख वोटर इंदौर क्षेत्र-5 में

सबसे कम वोटर इंदौर-3 में, नए वोटरों की संख्या 66 हजार से ज्यादा

इंदौर। जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया (एसआईआर) है। अंतिम सूची के अनुसार, जिले में 24,86, 996 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इनमें 12,52,332 पुरुष, 12,34569 महिला, 95 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता शामिल हैं। जिले का समग्र जेंडर रेश्यो 986 दर्ज किया गया।

यह जानकारी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवजीवन विजय पवार सहित संबंधित अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विधानसभा-3 सबसे कम वोटर– अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार, जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है। देपालपुर (203) में 2,55,354, इंदौर-1 (204) 3,11,268, इंदौर-2 (205) 2,89,962, इंदौर-3 (206) 1,54,131, इंदौर-4 (207) 2,18,147, इंदौर-5 (208) 3,52,849, डॉ अंबेडकर नगर (महू 209) 2,66,115, राऊ (210) 3,38,544, सांवेर (211) 3,00,626 हैं।

दावे, आपत्तियों का निपटारा– बैठक में बताया गया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान फार्म-6 के 79,660 आवेदन मिले, जिनमें से 71,114 मंजूर हुए। फार्म-7 के 6,796 आवेदन मिले, जिनमें से 5,959 मंजूर हुए। फार्म-8 के 54,928 आवेदन मिले, जिनमें से 49,396 मंजूर हुए। इस प्रकार कुल 1,41,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,26,469 आवेदन स्वीकार किए गए।

अंतिम सूची तक बढ़े मतदाता– अधिकारियों ने बताया कि 23 दिसंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 24,20,171 मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण और दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 24,86,996 हो गई है। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, समयबद्धता और दावों-आपत्तियों के निष्पक्ष निराकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

वकील को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर सेक्सटॉर्शन की धमकी दी गई

पश्चिम बंगाल की सिम से कॉल किया और क्लिप भेजी गई

इंदौर। शहर में साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग का एक नया मामला सामने आया है। वकील को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए फंसाकर पैसे वसूलने की कोशिश की गई। आरोपियों ने एडिट की हुई अश्लील क्लिप भेजकर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी।

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना एमआईजी थाना क्षेत्र की है। फरियादी राहुल पिता राजेन्द्र शोती निवासी देवनगर ने बताया कि 20 फरवरी को उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाली ने खुद को किसी कानूनी मामले में सलाह लेने वाली युवती बताया। बातचीत के दौरान वीडियो स्क्रीन पूरी तरह धुंधली रही और सामने वाला साफ दिखाई नहीं दिया।

चंद सेंकड में कॉल कटा – कुछ ही सेकंड बाद कॉल अचानक कट गया। इसके तुरंत बाद उसी नंबर से आपत्तिजनक वीडियो क्लिप भेजी गई। आरोप है कि क्लिप में वकील के वीडियो हिस्से को एडिट कर अश्लील दृश्य जोड़ दिए गए थे। साथ ही उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े मित्रों की आईडी के स्क्रीन शॉट भी भेजे गए। मैसेज के जरिए आरोपियों ने धमकी दी कि यदि तय रकम ट्रांसफर नहीं की गई, तो यह वीडियो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दिया जाएगा। जांच में पता चला कि जिन मोबाइल नंबरों से कॉल और मैसेज किए गए, उनकी सिम पश्चिम बंगाल से जारी हुई है। फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

धमकाने वाले बदमाश का जुलूस निकाला

इंदौर। द्वारकापुरी क्षेत्र में डेढ़ करोड़ रुपए के प्लॉट के बदले व्यवसायी को धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने व्यवसायी से 40 लाख रुपए देने और पुराने विवाद में समझौता करने के लिए धमकी दी थी। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने प्रेम प्रजापति निवासी विदुर नगर के खिलाफ धमकी और अड़ीबाजी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसे क्षेत्र से हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने खुद को छोड़ने के लिए युवा मोर्चा से जुड़े कुछ नेताओं के फोन पुलिसकर्मियों को करवाए। पुलिस पर उसे छोड़ने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी। प्रेम ने सौरभ राठौर को किशोर हटकर उर्फ भाऊ के नाम से धमकी दी थी। थाने में भी आरोपी के मोबाइल पर किशोर के इंटरनेट कॉल आते रहे। मोबाइल में किशोर, तब्बू और राजेंद्र नाम से रिकॉर्डिंग मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रेम के खिलाफ जमीन कब्जा, धोखाधड़ी, मारपीट और हत्या सहित करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। शनिवार शाम पुलिस ने उसका क्षेत्र में जुलूस निकाला।

साइबर ठगी की दो वारदात हुई

इंदौर। जालसाजों ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में युवक और महिला को निशाना बनाकर लाखों रुपए की साइबर ठगी की। पुलिस ने दोनों मामलों में साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। चंदन नगर थाना क्षेत्र निवासी जुनैद पिता शब्बीर खान के साथ 16 फरवरी की शाम ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई। जुनैद घर पर ही थे, तभी उनके मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे कटने के मैसेज आने लगे। पहले 99,999 रुपए, फिर 30,000 रुपए और आखिर में 4,000 रुपए। इस तरह कुल 1,33,999 रुपए करीब 1.34 लाख रुपए खाते से पार कर दिए गए। पुलिस अब उन खातों और ट्रांजेक्शन लिंक की जांच कर रही है, जिनके माध्यम से रकम ट्रांसफर हुई। दूसरे मामले में लसूड़िया थाना क्षेत्र के बजरंग नगर कांकड़ में रहने वाली मनसा बाई पति मोहन भारद्वाज भी साइबर ठगी का शिकार हुई। 15 फरवरी को अज्ञात जालसाजों ने उन्हें किसी बहाने झांसे में लिया और उनके खाते से 2 लाख रुपए का अवैध ट्रांजेक्शन कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल ट्रेल खंगाली जा रही है।

टेस्टिंग असिस्टेंट को ठेकेदार ने पीटा

इंदौर। बिजली कंपनी परिसर में विवाद कर रहे ठेकेदार को बाहर जाने का कहना टेस्टिंग असिस्टेंट को भारी पड़ गया। ठेकेदार ने असिस्टेंट को थप्पड़ मार दिया। बाणगंगा पुलिस को फरियादी लोकेश साहू निवासी केट रोड एमपीईबी में टेस्टिंग असिस्टेंट के पद पर पदस्थ है। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे वह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि परिसर में दो ठेकेदार, चेतन पाठक और मूरत सिंह झगड़ा कर रहे थे। लोकेश ने बाहर जाकर दोनों को अनुशासन बनाए रखने और परिसर से बाहर जाकर विवाद करने की हिदायत दी। समझाने के बाद वह वापस अपने ऑफिस में आ गए, लेकिन आरोपी ठेकेदार चेतन निवासी भौंरासला को यह बात नागवार गुजरी। वह फरियादी के ऑफिस में घुसा और बोला, तुम होते कौन हो, हमें बाहर जाने के लिए बोलने वाले! फरियादी ने जब अपना परिचय दिया कि वह शासकीय कर्मचारी है, तब भी आरोपी ने मर्यादा का उल्लंघन किया। जब फरियादी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने आव देखा न ताव और उनके गाल पर जोरदार चांटा जड़ दिया। जाते-जाते आरोपी ने धमकी दी कि अगर दोबारा मुझसे उलझे तो जान से खत्म कर दूंगा।

फोन पर करणी सेना के नेता को जान से मारने की धमकी मिली

● कॉल करने वाला नंबर मंदसौर के युवक के नाम रजिस्टर्ड

इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र में करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री मानसिंह राजावत को मोबाइल कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी 20 फरवरी की रात दी। मामले में शनिवार को हीरानगर थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हीरानगर पुलिस के अनुसार मारुति नगर निवासी मानसिंह राजावत को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनका नाम पूछने के बाद अपशब्द कहे और बच्चों की हत्या करने और खजराना क्षेत्र में आने पर जान से मारने की धमकी दी। मानसिंह राजावत ने पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। उन्होंने यह रिकॉर्डिंग वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजी और इसके आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल करने वाले नंबर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मंदसौर निवासी के नाम पर नंबर– पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस नंबर से कॉल किया गया, वह मंदसौर निवासी मरहूफ कादरी मंसूरी के नाम पर दर्ज है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। मानसिंह राजावत पिछले करीब 15 सालों से संगठन से जुड़े हैं। उनके अनुसार उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। एक बार उनके घर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला भी किया था। मानसिंह ने कुछ दिन पहले लसूड़िया क्षेत्र में एक ड्रग पेडलर के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। इसके अलावा तिलक नगर में छेड़छाड़ और अन्य मामले में भी पुलिस कार्रवाई करवाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस के फेरे विस्तारित

इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित किए जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है। मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल का अंतिम फेरा 27 फरवरी तक निर्धारित है, लेकिन, अब ये ट्रेन 27 मार्च तक मुंबई सेंट्रल से चलेगी। इसी प्रकार इंदौर-मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल का अंतिम फेरा 28 फरवरी निर्धारित है, पर अब इसे 28 मार्च तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन, दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। गाड़ी संख्या 09085 और 09086 मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से शुरू है।

चेक चुराकर फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से पौने 5 लाख रु निकाले

● मालिक का विश्वास जीता और हरकत की, दो पकड़ाए

इंदौर। दुकान के ड्राज से चेक चुराकर बदमाशों ने फर्जी हस्ताक्षर कर पौने पांच लाख रुपए निकाल लिए। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपियों ने मालिक का भरोसा जीतकर उन्हें धोखा दिया। सेंट्रल कोतवाली पुलिस को फरियादी नवीन राजपाल निवासी आस्कर कॉलोनी ने बताया कि 24 नवंबर को उनके मोबाइल पर मैसेज आया, जिससे पता चला कि उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते से 4,80,000 रुपए किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। बैंक से जानकारी लेने पर खुलासा हुआ कि चेक क्रमांक 002222 के जरिए राशि निकाली गई थी। जांच के दौरान पता चला कि यह रकम उज्जैन निवासी सुनील पिता आनंद कुमार मिश्रा (24) निवासी निजातपुरा उज्जैन के खाते में जमा हुई है। तकनीकी साक्ष्यों और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने साथी पीयूष पिता लोकेश चौहान (22) निवासी बाणगंगा के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दुकान में काम करते हुए मालिक का विश्वास जीता और शास्त्री मार्केट स्थित दुकान के दराज में रखा चेक चुरा लिया। इसके बाद फर्जी हस्ताक्षर और राशि भरकर चेक बैंक में लगाकर राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

शाजापुर से इंदौर आए युवक की जेब काटने वाले दो को पकड़ा

● युवक का ध्यान भटकाकर सिटी यात्री बस में वारदात की

इंदौर। शाजापुर से सेनेटरी का सामान खरीदने आए युवक की जेब से बदमाशों ने 50 हजार रुपए निकाल लिए। युवक से साथ बस में वारदात हुई थी। घटना के पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश भीड़भाड़ वाले इलाके में लोगों को ध्यान भटकाकर वारदात कारित थे। सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी रवीन्द्र पाराशर के अनुसार, फरियादी केसर सिंह निवासी ग्राम गिरवर थाना लालघाटी,जिला शाजापुर 14 फरवरी को शाजापुर से इंदौर सेनेटरी सामान खरीदने के लिए आए थे। वे पीपल्याहाना से सिटी बस में बैठकर पालिका प्लाजा एमटीएच कंपाउंड के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनके होश उड़ गए। जेब से 50 हजार रुपए गायब मिले।

छह दिन बाद कराई शिकायत– काफी तलाश के बाद भी रुपए नहीं मिलने पर उन्होंने 20 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने टीम गठित कर जांच शुरू कराई। टीम ने घटनास्थल और बस में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी अमर सिंह निवासी मेघदूत नगर और राजेश सिंह निवासी ग्राम गिरोता (देपालपुर) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 28 हजार रुपए जब्त किए हैं।

ऐसे देते वारदात को अंजाम– पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बाहरी यात्रियों को निशाना बनाते थे। सिटी बस, ऑटो रिक्शा, बस स्टॉप और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहले रैकी कर व्यक्ति की पहचान करते, फिर ध्यान भटका कर घेराबंदी करते हुए जेब से नकदी पार कर देते थे। आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की है।

प्रेमिका छात्रा का मोबाइल हैक कर डेटिंग एप की चैट पढ़ता था पीयूष

● पीयूष का परिवार राजी नहीं था, पर दोनों ने कमरे में शादी की

इंदौर। एमबीए छात्रा की हत्या के आरोपी प्रेमी पीयूष धामनोदिया से द्वारकापुरी पुलिस पूछताछ कर रही है। पीयूष बुधवार तक पुलिस की रिमांड में है। उसकी मनःस्थिति ठीक नहीं है। कभी गुमसुम रहता है, कभी रोता है या बैठा-बैठा हंसने लगता है।

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार मंदसौर निवासी पीयूष की छात्रा से पिछले साल सितंबर में ही दोस्ती हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में एक कक्षा में पढ़ते थे। पीयूष छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। छात्रा के परिवार ने तो दोनों की शादी के लिए कॉल भी लगाया था। इसके बाद जनवरी में पीयूष ने रूम पर ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया और दीपक को साक्षी मानकर शादी कर ली।

छात्रा का मोबाइल हैक किया – इसके बाद भी वह छात्रा पर शक करने लगा। उसने छात्रा का मोबाइल हैक कर लिया और उसकी चैटिंग पढ़ने लगा। छात्रा को कुछ युवकों से बात करते हुए भी देख लिया था। एक डेटिंग एप पर भी छात्रा की आईडी बनी हुई थी। इससे खफा पीयूष छात्रा को मारने की साजिश करने लगा। 10 फरवरी को रूम पर ले गया और दोनों बातचीत करने लगे। छात्रा ने आर्थिक परेशानी साझा की और कहा कि छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड अपडेट करना है। पीयूष ने उसको आश्वासन दिया और झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने छात्रा के मजाक-मजाक में हाथ-पैर बांधे और सीने पर बैठकर गला घोंट दिया। बच न सके इसलिए चाकू घोंप भी घोंप दिया।

छात्रा की फोटो के आगे फूल – टीआई मनीष मिश्रा के अनुसार मोबाइल जब्ती के लिए आरोपी को मुंबई ले जाया जाएगा। उसने मुंबई के नाला सोपारा में छात्रा की आत्मा बुलाने के लिए टोने-टोटके की क्रिया भी की थी। यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर उसने छात्रा की फोटो के आगे फूल, खाने का सामान, मिठाई, हल्दी, कुमकुम आदि रखा था।

आत्महत्या इसलिए नहीं की – पीयूष ने कहा कि छह महीने पूर्व छात्रा से दोस्ती हुई तो उसने पुराने दोस्तों की सब बातें बता दी थीं। उसने कहा था कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन चैटिंग से पता चला कि वह उनसे अभी भी बात करती है। मुझे लगा वह मुझसे कुछ छुपा रही है। उनकी तरह मुझे भी छोड़ सकती है। मैंने हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का सोच लिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुंबई में पुल से भी कूदना चाह रहा था। मगर सच बताने के लिए रुक गया। मुंबई में ही नौकरी करना चाहता था। पर्चे और बोर्ड पर नंबर देखकर कुछ एजेंसी से बात भी कर ली थी।

संपादकीय

यूथ कांग्रेस का अभद्र विरोध

देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित पांच दिनी अंतरराष्ट्रीय एआई इम्पेक्ट समिट के अंतिम दिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह भारत मंडपम् में घुसकर और अर्द्धनग्न होकर मोदी सरकार का विरोध किया, उससे पूरी दुनिया में भारत को लेकर गलत संदेश गया है। ये कार्यकर्ता भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस इसका विरोध शुरू से कर रही है और पार्टी के नेता राहुल गांधी तो इसे ट्रंप के आगे पीएम मोदी का समर्पण कई बार बता चुके हैं, फिर भी केवल दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो अभद्र प्रदर्शन यूथ कांग्रेस नेताओंने किया, उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि इस घटना के बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से जवाबी हिंसक प्रदर्शन किया, उसने यूथ कांग्रेसियों के बचकाने विरोध प्रदर्शन से भाजपा को मिले राजनीतिक माइलेज को कम ही किया है। कांग्रेस मोदी सरकार का लगातार विरोध कर रही है, विपक्ष के नाते यह उसका अधिकार भी है, लेकिन वो इस हद तक नीचे जाएगी, यह उम्मीद नहीं थी। चंद कांग्रेसियों को छोड़ दें तो इस अर्द्धनग्न प्रदर्शन का किसी विपक्षी पार्टी ने भी समर्थन नहीं किया। क्योंकि यह समिट केवल मोदी सरकार की नहीं समूचे भारत वर्ष और भारतीयों की प्रतिष्ठा का प्रश्न थी। कांग्रेस को विरोध ही करना था तो वह बाहर कहीं या जंतर मंतर पर भी किया जा सकता था। शालीन विरोध के लिए लोकतंत्र में जगह हमेशा से है। बताया जाता प्रदर्शनकारी सुरक्षा व्यवस्था को झांसा देकर भीतर घुसे और बाद में अपनी टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोगों ने उनकी धुनाई भी की। बाद में पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। कार्यकर्ताओं ने किसी के साथ मारपीट नहीं की। उल्टे प्रदर्शनकारियों की ही पिटाई की गई । उन पर लगाई गई धाराएं अन्य राजनीतिक दलों के लिए उदाहरण सेट करने की कोशिश हैं। पुलिस का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश और नेपाल के जेन जी की तर्ज पर करने की कोशिश थी। इस घटना के बाद भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से हंगामा किया ये देश की छवि खराब करने की कोशिश है। कांग्रेस देश का मान सम्मान भूल गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस पार्टी पर शर्म आती है। राहुल गांधी के निर्देश पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन में हंगामा किया। भारत विरोधी कांग्रेस। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस शहरी नक्सलियों की तरह व्यवहार कर रही है!' उधर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, और हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस भले अपने इस कृत्य को जायज ठहराने की कोशिश करे, लेकिन देश में अधिकांश लोगों ने इस कृत्य को निंदाजनक ही माना है। वैसे कांग्रेस भारत अमेरिका उस ट्रेड डील को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जिसका अंतिम ड्राफ्ट अभी सामने आया ही नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दूसरे देशों पर मनमाने टैरिफ लगाने को खारिज कर दिया है। उसके बाद ट्रंप ने नए सिरे से 15 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। अब आगे क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी हरकत उस कांग्रेस ने की है, जो बरसो देश की सत्ता पर काबिज रही है और आगे भी दावेदार है। ऐसी पार्टी से देश जिम्मेदारी भरे आचरण की अपेक्षा करता है, न कि ऐसे अभद्र प्रदर्शन की।

संसद का सामना करें प्रधानमंत्री

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

संसद के सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होती है जिसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों भाग लेते है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण को संसद की सहमति प्रदान की जाती है। दरअसल यह परिपाटी है, जिसके माध्यम से सरकारें अपनी नीतियों और कार्यकर्मों को सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हैं और विरोधी दल उसकी मीमांसा या आलोचना करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति अमूमन संसद के उसी बहुमत वाले दल के होते हैं जिसकी सरकार होती है और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सरकार ही तैयार करती है जिसे वे पढ़ते हैं, याने एक अर्थ में यह सरकारी भाषण होता है। यह स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के लोग उसका समर्थन करें और प्रतिपक्ष विरोध में बोले, हालांकि होना तो ये चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का अभिभाषण ना बनाया जाए तथा उस पर चर्चा तो हो परंतु उस पर मतदान न लिया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को इतनी स्वतंत्रता मिले कि वह निष्पक्षता से अपने मन की बात कह सके। अगर आवश्यक हो तो सत्ता पक्ष को भी आवश्यक सुधार या विचार के लिए शामिल किया जा सके। अगर यह परंपरा बने तो यह सरकारों के स्वास्थ के अनुकूल होगा, प्रतिपक्ष के लिए भी होगा और राष्ट्रपति के भाषण की राष्ट्रीय गरिमा होगी जो एक प्रकार से सरकार और प्रतिपक्ष दोनों के लिए मार्गदर्शक होगा इससे आम जनता की भी दिलचस्पी संसदीय कार्य में बढ़ेगी परंतु परंपरा आजादी के बाद से यही चली आ रही है।

इस बार भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में चर्चा शुरू हुई और परंपरा के विपरीत प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में कहे गए बिंदुओं पर कम तथा इस अवसर को सरकार की आलोचना का ऐकान्तिक माध्यम बनाया। आम परंपरा रही है कि जब प्रतिपक्ष की ओर से आलोचना की जाती है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाए जाते है तब उसका उत्तर प्रधानमंत्री देते हैं परंतु इस परंपरा को तोड़ दिया गया, एक तो सरकार की ओर से उत्तर गृहमंत्री अमित शाह ने दिया, जबकि प्रधानमंत्री संसद ही नहीं पहुंचे। हालांकि वे दिल्ली में थे पर बाद में उन्होंने राज्य सभा में उत्तर दिया। वह भी आमसभा जैसा भाषण था, याने जिस शैली में प्रतिपक्ष ने आलोचना की थी उसी शैली में उनका उत्तर था जिसमें उठाये गए बिंदुओं पर चर्चा लगभग नहीं थी, बल्कि व्यंग, आलोचना और हँसी मजाक ज्यादा था। संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपरा का जैसा चीर हरण इस बार हुआ है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। वरना पहले प्रधानमंत्री महोदय संसद में आकर स्वतरू संसद में प्रतिपक्ष के भाषण सुनते थे, प्रतिपक्ष द्वारा उठाये मुद्दों को सुनते थे और उस पर उत्तर देते थे। कुछ संवाद होता था इस बार तो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को स्पीकर ने बोलने से ही रोक दिया। मैं इस बहस पर नहीं जाऊँगा कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण कितना सुसंगत था, राष्ट्रपति के भाषण पर केंद्रित था या नहीं और कितना असंगत था और विषय से हटकर था। स्पीकर महोदय को यह अधिकार है कि वे असंगत बातों को या असंसदीय बातों को लोकसभा की कार्यवाही से निकाल सकते है और भविष्य में वे कार्यवाही का हिस्सा नहीं होती। परंतु नेता प्रतिपक्ष, जो एक संवैधानिक पद होता है को बोलने से प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, परंतु इस बार स्पीकर ने स्वतः यह असंसदीय व्यवहार किया।

मैं आमतौर पर टीवी नहीं देखता हूँ परंतु उस दिन की

संसदीय कार्यवाही बाद में स्वतः भी देखी ताकि मेरे निष्कर्षों में कोई त्रुटि ना हो। अन्य लाखों लोगों की तरह मैंने भी यह महसूस किया की नेता प्रतिपक्ष का भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुद्दों से हटकर था और स्पीकर का व्यवहार एक लोकतांत्रिक संस्था के अध्यक्ष जैसा नहीं बल्कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जैसा था जो संसदीय तो बिल्कुल नहीं था बल्कि एक तानाशाह जैसा था। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री जी को उठाये गए सवालों का उत्तर देना चाहिए था परंतु वे उत्तर देने नहीं आये इस पर भी उनकी आलोचना हुई। क्योंकि आजादी के बाद यह पहला घटनाक्रम था जब प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर देने नहीं आये और इसके विपरीत वे राज्यसभा में उत्तर देने गए। इसकी सफाई में उनकी तरफसे बाद में स्पीकर महोदय ने यह सार्वजनिक रूप से कहा कि प्रधानमंत्री जी को आने से मैंने ही रोका था, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था। स्पीकर का यह बयान भी संवैधानिक और संसदीय परंपरा के खिलाफ है। इस अर्थ में चिंताजनक भी है कि क्या संसद भवन के अंदर प्रतिपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पर कोई शारीरिक हमला हो सकता था। परंतु मुझे लगता है और शायद मेरे ख्याल से देश में कोई विश्वास नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी लोकसभा के अंदर शारीरिक हमले का खतरा था। अगर स्पीकर महोदय को ऐसी कोई सूचना थी तो वे सदन के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय कर सकते थे। अगर धरना देते या नारे लगाते सांसदों को बाहर धकेल कर निकालने के लिए मार्शलों का प्रयोग हो सकता है तो क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं हो सकता था। फिर यह भी सोचना चाहिए कि अगर प्रतिपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पर हमला होता तो क्या प्रतिपक्ष देश में मुंह दिखाने के काबिल रहता? मुझे लगता है की अगर कभी ऐसी गलती प्रतिपक्ष करता तो इसका भारी खामियाजा प्रतिपक्ष को चुकाना पड़ता। एक बार मध्य प्रदेश की विधान सभा में जनसंघ के एक विधायक (जो आर एस एस के थे) पंढरी राव कृदत्य ने विधान सभा में जूता फेंका था और उस जूता कांड ने तत्कालीन जनसंघ को सार्वजनिक रूप से इतनी निंदा का पात्र बनाया था कि वे घुटना टेक जैसे हो गए थे। उनका एक प्रकार का सार्वजनिक और सामाजिक बहिष्कार जैसा हो गया था। कई वर्षों तक उस कांड ने जनसंघ को उभरने नहीं दिया था। फिर प्रधानमंत्री जी का जिस संस्था से संबंध है उस संस्था के लोग तो हिंदू रक्षक अपने आप को कहते हैं और उन्हें बचपन से शारीरिक व्यायाम और लाठी चलाने का अभ्यास होता है। क्या ये बहादुर हिंदू रक्षक अपने प्रधानमंत्री की रक्षा, अल्पसंख्यक प्रतिपक्ष से नहीं कर सकते? और एक महत्वपूर्ण पक्ष तो ये भी है कि क्या किसी स्पीकर को प्रधानमंत्री को संसद में रोकने का ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है? क्या संसद बगैर प्रधानमंत्री के चल सकती है? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनसे इस आशंका के आधार पर नहीं आने की कोई अनुमति ली थी या यह स्वतः स्पीकर द्वारा रचित कूट कहानी है? जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री को संसद की अवमानना के अपराध से बचाना था। अगर कोई मजबूत रीड की हड्डी वाला स्पीकर होता तो वह प्रधानमंत्री को संसद में उपस्थित होकर उत्तर देने का निर्देश देता। इस घटना ने प्रधानमंत्री जी को भी संसदीय परम्परों को तोड़ने के अपराध में कठघरे में खड़ा किया और स्पीकर महोदय को भी।

दरअसल जो प्रश्न उस दिन प्रतिपक्ष के द्वारा संसद में उठाये गए थे वे ऐसे थे कि जिनसे प्रधानमंत्री जी बचना चाहते थे। एपस्टीन फाइल्स में उनका नाम आया है, मैं नहीं जानता हूँ कि यह सही है या गलत है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की सूचनायें आ रही हैं और उनके आधार पर एकदम प्रामाणिक रूप से कुछ भी कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। उसके बारे में प्रधामंत्री जी ही वस्तु स्थिति से अवगत करा सकते हैं। क्या वे एपस्टीन के उस अपराधग्रह में गए थे? अगर नहीं गए है तो कुछ कहना नहीं है परंतु अगर गए है तो उनका उद्देश्य क्या था, यह सफाई तो वे ही दे सकते है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी तो इतने प्रचार चेता है तथा फोटो खिंचवाने और छपवाने के शौकीन हैं कि वे मंदिर में जाकर आँख बंद कर प्रार्थना करते हैं और उसकी भी फोटो देश में छप जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने एप्स्टीन के ऐयाशग्रह में जाकर बात करते हुए या पूजा पाठ से लेकर जो भी उन्होंने किया हो, उसके फोटो डलवा देते तो शायद किसी को आपत्ति करने का अवसर नहीं मिलता और अगर वे नहीं गए है तो उन्हें संसद में खंडन करना चाहिए। चुप्पी और छिपाव संशय पैदा करता है। प्रधानमंत्री की चुप्पी और स्पीकर महोदय के रहस्य उद्घाटन के बाद तो और अधिक संशय पैदा हो गया है फिर अगर लोकसभा में उन्हें खतरा था तो क्या वह खतरा प्रतिपक्ष की ओर से राज्यसभा में नहीं था? क्या वे ऐसा मानते हैं कि निर्वाचित लोग जो दस लाख जनता के मतों से चुन के आये हैं, वे अपरिहार्य रूप से अपराधी होते हैं और जो दलों के गुटीय नेताओं द्वारा नामजद होकर राज्यसभा में आये है वे सब सज्जन लोग होते हैं?

मेरे पड़ोस में एक मध्य वर्गीय परिवार रहता है उनके घर में एक छोटा बच्चा है जो शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसे जिस दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता तो वह अपने पिता से कहता है कि पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा मुझे साथ पढ़ने वाले बच्चे मार देंगे और उसके मम्मी पापा कहते हैं आज मत जाओ कल चले जाना। हुबहू यही चित्र मेरे आँखों के सामने आ गया, जब मैंने स्पीकर महोदय का बयान पढ़ा कि जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हो कि स्पीकर महोदय आज मैं संसद में नहीं जाऊँगा मुझे प्रतिपक्ष के सांसद मारेंगे और स्पीकर महोदय उसी माता पिता के स्वर में कह रहे है कि कोई बात नहीं आज मत आओ कल राज्यसभा में आ जाना। जो भी हो इस घटना ने प्रधानमंत्री और स्पीकर के आचरण और संसदीय आचरण का मुखौल उड़ा दिया है।

ग्रीन फ्रेमवर्क का दावा और जलवायु संकट

मध्यप्रदेश बजट

राजेश कुमार

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में 2026-27 का रू. 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया। इसे राज्य का पहला ग्रीन बजट ढांचा बताया गया, लेकिन वास्तविक आवंटन में जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर कमियाँ दिखाई देती हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए मात्र रू. 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के रू. 39 करोड़ से लगभग 20 प्रतिशत कम है। वहीं वन संरक्षण हेतु रू. 6,121 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। यह विरोधाभास स्पष्ट करता है कि सरकार वन संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन व्यापक पर्यावरणीय और जलवायु संकट को नजरअंदाज कर रही है।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि बजट में जलवायु परिवर्तन के लिए कोई स्पष्ट बजट लाइन नहीं दी गई है। न तो अनुकूलन (Adaptation) और न ही शमन (Mitigation) कार्यक्रमों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। कुल बजट का मात्र 0.007 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जा रहा है, जो नगण्य है।

यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2022 से 2025 तक मध्यप्रदेश ने 598 दिनों में गंभीर मौसम का सामना किया, यानी लगभग हर तीसरे दिन। इस दौरान 1,439 लोगों की मौत हुई, 82,170 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं, 20,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए और 6,000 पशुओं की मृत्यु हुई। वर्ष 2024 में ही प्रदेश ने 176 चरम मौसम वाले दिन दर्ज किए, जिनमें 353 लोगों की मौत हुई और 25,170 हेक्टेयर प्रभावित हुए।

अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश की स्थिति और भी कमजोर दिखती है। राजस्थान ने अपने पहले ग्रीन बजट 2025-26 में कुल निधियों का 11.34 प्रतिशत सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के लिए आवंटित किया। गुजरात ने जलवायु परियोजनाओं के लिए रू. 165 करोड़ का प्रावधान किया। इसके विपरीत मध्यप्रदेश ने पर्यावरण बजट घटा दिया और जलवायु परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं किया।

राज्य ने हाल ही में मध्यप्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन क्रियान्वयन योजना 2023-28 तैयार की है, जिसमें रू. 97,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। लेकिन पर्यावरण विभाग का बजट मात्र रू. 31 करोड़ है। यह गंभीर असमानता दर्शाती है कि कार्ययोजना के वित्तपोषण को लेकर स्पष्टता नहीं है। संभावित धन स्त्रोतों–केंद्रीय योजनाएँ, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त, निजी निवेश–का उल्लेख अस्पष्ट है। इस अनिश्चितता के कारण कार्यान्वयन बाधित होता है।

बजट में आपदा राहत के लिए रू. 715 करोड़ और राज्य आपदा निधि हेतु रू. 564 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन इनमें भी जलवायु दृष्टिकोण का समन्वय नहीं दिखता।

यह स्पष्ट है कि सरकार जलवायु संकट की गंभीरता को प्राथमिकता नहीं दे रही है। जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए निवेश बढ़ा रही है, तब मध्यप्रदेश सरकार बिना जलवायु परिवर्तन का नाम लिए बजट पारित कर रही है। इसका सबसे बड़ा असर हाशिए पर खड़े समुदायों–दलित, आदिवासी, किसान, मछुआरे, महिला समूह, दिव्यांग और एलजीबीटीक्यू समुदाय पर पड़ रहा है, जो सीधे जलवायु आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं और जिनके पास संसाधनों की भारी कमी है।

मध्यप्रदेश का 2026-27 बजट ग्रीन बजट कहलाने के बावजूद जलवायु संकट से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति प्रस्तुत नहीं करता। यह न केवल सरकार की गंभीरता की कमी को दर्शाता है बल्कि भविष्य में बढ़ते जलवायु संकट से निपटने की क्षमता को भी कमजोर करता है। सरकार को चाहिए कि वह एक स्पष्ट बजट लाइन, समर्पित वित्तीय रणनीति और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करे, ताकि जलवायु कार्ययोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और कमजोर समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

बाजारीकरण की भेंट चढ़ गया 'आदिवासी उत्सव'

भोंगर्या

अनिल तंवर

(आदिवासी संस्कृति के जानकार)

भोंगर्या की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। रियासत काल से ही यह पर्व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। कुछ इतिहासकार इसे ग्राम 'भगोर' से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे 'गुलालिया हाट' का विकसित रूप मानते हैं। मान्यता चाहे जो भी हो, लेकिन इसका स्वरूप हमेशा से सामुदायिक रहा है। ढोल, मांदल और बांसुरी की वह मिश्रित ध्वनि जब पहाड़ों से टकराती है, तो वह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की नहीं, बल्कि 'मानवता के आदिम संगीत' की आवाज़ होती है।

जब फागुन की बयार चलती है, महुए की मादक गंध हवाओं में घुलने लगती है और आम की मंजरियों से अंचल महक उठता है, तब आलीराजपुर, झाबुआ और धार की पहाड़ियों में एक गूँज सुनाई देती ढोल और मांदल की थाप। यह थाप संकेत है 'भोंगर्या' यानी भगोरिया के आगमन का। लेकिन, दुर्भाग्य देखिए, जिस पर्व को आदिवासी समाज अपनी अस्मिता और खुशहाली का प्रतीक मानता है, उसे बाहरी दुनिया और गैर-जिम्मेदार मीडिया ने 'प्रेम-प्रसंगों' और 'वैलेंटाइन डे' जैसे सतही शब्दों के जाल में उलझा दिया। आज वक्त है कि भोंगर्या के उस असली चेहरे को दुनिया के सामने रखा जाए, जो बाज़ारीकरण और छपास की भूख वाले फोटोग्राफरों की नज़रों से ओझल हो गया।

भगोरिया, जिसे स्थानीय भाषा में 'भोंगर्या' कहा जाता है, महज़ एक साप्ताहिक हाट नहीं है। यह होली के पावन पर्व से ठीक सात दिन पहले शुरू होने वाला एक उत्सव है। यह वह समय है जब खेत कट चुके होते हैं, खलिहान भरे होते हैं और प्रकृति अपने चरम यौवन पर होती है। आदिम संस्कृति में यह 'सृजन' और 'आभार' का पर्व है। आलीराजपुर जिले के ग्रामों में लगने वाले ये हाट करीब 55 किलोमीटर की परिधि में फैले होते हैं, जहां कदम-कदम पर संस्कृति की नई छटा देखने को मिलती है।

पिछले कुछ दशकों में एक सोची-समझी साजिश या अज्ञानता के कारण भोंगर्या को 'परिणय पर्व' के रूप में प्रचारित किया गया। कुछ बाहरी लेखकों और मीडिया संस्थानों ने इसे 'लड़की भगाने वाला मेला' बताकर आदिवासी समाज की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। सत्य यह है कि पान खिलाना या गुलाल लगाना कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं, बल्कि सामाजिक उल्लास का एक हिस्सा मात्र है। आदिवासी समाज की अपनी एक मर्यादा और अनुशासन है। यहां युवक-युवतियाँ सज-धजकर आते ज़रूर हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी संस्कृति का प्रदर्शन और सामूहिक नृत्य में सहभागिता करना होता है। 'वैलेंटाइन डे' जैसे पश्चिमी शब्दों से इसकी तुलना करना

आदिवासी जीवन दर्शन के साथ मजाक है। नई पीढ़ी के जागरूक युवा अब इस भ्रामक प्रचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उनकी मांग जायज है हमारी परंपरा को अपनी गंदगी भरी नज़रों से मत देखो।

मैदानी हकीकत यह है कि इस क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत जनता पेट की आग बुझाने के लिए पलायन करती है। साल भर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में मजदूरी करने वाले ग्रामीण इस पर्व की महक पाते ही अपनी जड़ों की ओर लौटने लगते हैं। भगोरिया उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज से दोबारा जुड़ने का एक 'सेतु' है। होली के पूजन के लिए गुड़, हार-कंगन और पूजा सामग्री की खरीदी के बहाने यहाँ रिश्तों का मेला लगता है। झूला-चकरी की मस्ती और ताड़ी का आनंद उनके साल भर के संघर्ष की थकान को मिटा देता है। यह वह समय है जब एक आदिवासी अपनी गरीबी और संघर्ष को भूलकर जीवन का उत्सव मनाता है।

भोंगर्या की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। रियासत काल से ही यह पर्व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। कुछ इतिहासकार इसे ग्राम 'भगोर' से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे 'गुलालिया हाट' का विकसित रूप मानते हैं। मान्यता चाहे जो भी हो, लेकिन इसका स्वरूप हमेशा से सामुदायिक रहा है। ढोल, मांदल और बांसुरी की वह मिश्रित ध्वनि जब पहाड़ों से टकराती है, तो वह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की नहीं, बल्कि 'मानवता के आदिम संगीत' की आवाज़ होती है। आज जब यह लोकपर्व 24 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक अपनी छटा बिखेरेगा, तब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 'सस्ती लोकप्रियता' और 'सनसनीखेज खबर' के चक्कर में एक गौरवशाली समाज को बदनाम न करे। फोटोग्राफरों को 'क्लोज-अप' लेने से पहले उस संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए।

आदिवासी समाज अब जागृत है। वह अपनी परंपराओं का संरक्षण करना भी जानता है और उनके अपमान का प्रतिकार करना भी। भोंगर्या हमें सिखाता है कि अभावों में भी कैसे मुस्कराया जाता है। यह पर्व हमारी विरासत है, इसे महज़ 'मेला' समझने की भूल न करें। भगोरिया की मादक धुन सभी को बुला रही है। इस पर्व को उस पवित्रता के साथ देखें, जिस पवित्रता के साथ एक आदिवासी मांदल पर थाप देता है। यह प्रेम का बाजार नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के मिलन का महाकुंभ है। इस वर्ष जब हम भगोरिया की खुशबू महसूस करें, तो यह प्रण लें कि हम भ्रामक प्रचार की गुलाल को अपनी आँखों से पोंछकर सच्चाई के दर्पण में इस महान संस्कृति के दर्शन करेंगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आये फल होय

व्यंग्य

सुधीर नायक

कर्तव्यनिष्ठ सबकुछ करता है पर निर्णय नहीं करता। वह क्वेरी करेगा,कमेटी बिठा देगा, जांच करवा लेगा, मौका मुआइना करवायेगा, रिपोर्ट मंगवायेगा,परीक्षण पर परीक्षण करवायेगा, तमाम जगह से ओपीनियन इकट्ठे कर लेगा-कुल मिलाकर मतलब यह है कि वह सारे धतकरम करेगा पर मामला खतम नहीं करेगा।उसके हाथ कांपते हैं। दो चार बार पेन खोल भी लेगा पर अंततः रख देगा। वह सबकुछ बेहतरीन लिखता है पर उससे फैसला नहीं लिखा जाता। फाइलों का डील-डौल ही बता देता है कि ये किसी कर्तव्यनिष्ठ की फाइलें हैं। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की फाइलें कभी कुपोषित नहीं मिलेंगी। भरी-पूरी,हृष्ट-पुष्ट मिलेंगी।नजब सबकुछ हो चुकता है, करने को कुछ नहीं रह जाता तो वह रि रि करने लगता है।रिओपीनियन, रिएक्ज़ामिन। फाइल फिर से रिरियाते हुए चल पड़ती है। मैंने एक बार कहा-साब,अब सबकुछ तो हो चुका। रि रि भी हो चुका। रि के बाद तो फ्री कर दो। हां कर दो या न कर दो।नवे बोले-तुम्हें तो मालूम है, मैं कर्त्तव्यनिष्ठ हूं।मैंने स्वीकार किया-हां आप कर्त्तव्यनिष्ठ तो हैं। आपको कर्त्तव्यनिष्ठ का पुरस्कार भी मिला है।वे बोले-तो फिर ऐसी बात क्यों करते हो? मैंने यह कब कहा कि मैं निर्णयनिष्ठ भी हूं। सरकार भी कर्तव्यनिष्ठ ही चाहती है।निर्णयनिष्ठ नहीं चाहती। मेरे कर्तव्य में कोई कमी हो तो बताइए।फाइल चलाना मेरा कर्तव्य है सो फाइल बदस्तूर चल रही है। एक भी दिन रुकी हो तो बताओ।मैं निरुत्तर हो गया।यह बात तो सच है कि उनके सामने फाइल रुकती कभी नहीं है। नआयी और गयी।नगयी और आयी। लेकिन यह सवाल मुझे वर्षों तक परेशान करता रहा कि आखिर इतना काबिल आदमी ज़रा सा निर्णय क्यों नहीं कर पाता? वे इतने जहीन हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी चुटकियों में समझा देंगे लेकिन आवेदक को राशन कार्ड मिलना चाहिए कि नहीं? इतनी मामूली सी बात फाइल पर नहीं समझा पाते।नफाइल चार सौ पेज की हो गयी पर वे चार लाइन नहीं लिख पाये। फाइल उनकी चार लाइनों को तरसती है।मैं अपनी इस जिज्ञासा को लेकर बड़े बड़े विद्वानों से मिला हूं। विद्वान और उलझा देते हैं।

एक विद्वान बोले-यह आध्यात्मिक विषय है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी आध्यात्मिक होता है।वह जानता है कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। निर्णय भगवान के हाथ में है। होइहि वही जो राम रचि राखा।नइंसान की क्या औकात कि वह फैसला सुनाये और यदि सुनाता है तो यह पाप है।वह धर्मभीरु है। पाप से डरता है,इसलिए निर्णय नहीं करता।जब तक रामजी का फैसला न आ जाए तब तक वह फाइल चलाता रहता है। अपना कर्म करता है।

दूसरे विद्वान ने बताया-यह नीतिगत मामला है।वह अधिकारी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है।लोग बार-बार आते हैं तो आफिस टूरिज्म बढ़ता है।लोगों को रोजगार मिलता है।कई पेट पलते हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है।नवह जो कर रहा है वह जनहित में है।

एक बार मुझे एक स्मार्ट लड़का मिला। वह विद्वान तो नहीं था पर उसने बड़ी पते की बात बतायी। उसने कहा-अंकल,सरकार जनता को फिट रखना चाहती है। यूं समझिए कि हर आफिस एक जबरदस्त जिम है।वैसे तो लोग जिम जाते नहीं। आफिस में काम पड़ जाये तो लोग छरहरे होकर निकलते हैं।वह खुद किसी आफिस में फंस गया था वहीं से स्मार्ट हुआ था। उसने बताया कि पहले वह थुलथुल था। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। न उसकी अर्ज़ी तो नहीं निपटी पर चर्बी निपट गयी।उसकी शादी हो गयी। वह आफिस के प्रति कृतज्ञ था।

इस तरह मुझे अनेक मत मिले पर मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैं अपनी जिज्ञासा लिए हुए ही इस दुनिया से चला जाता यदि गोयल साब का सत्संग लाभ नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान गोयल साब से मिला।गोयल साब ने सारी थ्योरीज़ को हवा में उड़ा दिया। वे उवाचे-वत्स,ये सब फालतू की बातें हैं। कौन कहता है डिसीज़न नहीं होते? रीज़न और सीज़न हो तो खूब डिसीज़न होते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की-अभी तुम सितंबर में देखना। सीज़न आयेगा।उड़कर डिसीजन होंगे। मैंने पूछा-क्यों? वे बोले-सितंबर से साहब की कोठी का काम लगेगा। ठेका अपने ही पास है। शीट जब नोट देती है तभी नोटशीट कहलाती है,पुत्तर।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

आरक्षण व्यवस्था गहन बहस और विमर्श का विषय

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं। साथ ही राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) के अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण 'उचित सीमा के भीतर' होना चाहिए। इसकी अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

हाल ही में हुई जाति जनगणना ने मौजूदा आरक्षण नीतियों की पर्याप्तता और निष्पक्षता पर चर्चा को और तेज कर दिया है। भारत में आरक्षण हमेशा से सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के चौराहे पर खड़ा रहा है। हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 राज्यों को ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने का अधिकार देते हैं। लेकिन, न्यायिक रूप से लगाई गई 50 प्रतिशत की सीमा अक्सर अधिक समावेशिता की मांगों से टकराती रही है। 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पर बहस पुनः शुरू हो गई तथा याचिकाएं और राजनीतिक मांगें अधिक कोटा और लाभों के उप-वर्गीकरण की मांग कर रही है। एक राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा को लचीला माना जाए, जिसे 'विशेष परिस्थितियों' में नजरअंदाज करने की अनुमति दी जाए। साथ ही राज्य सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले कानून को मान्य करने की मांग की है। हाल के राजनीतिक बयान, जैसे कि बिहार में 85 प्रतिशत आरक्षण की मांग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रीमी लेयर प्रावधानों की मांग करने वाली सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं, समानता की संवैधानिक गारंटी के साथ सकारात्मक कार्रवाई को संतुलित करने की जटिलता को उजागर करती है।

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं। साथ ही राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) के अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण 'उचित सीमा के भीतर' होना चाहिए। इसकी अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होनी चाहिए। क्योंकि, इसे औपचारिक समानता बनाए रखने के रूप में देखा गया था। भारतीय संवैधानिक कानून के अंतर्गत सबसे चर्चित मामलों में से एक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) था। इसे 'मंडल मामला' भी कहा जाता है। मंडल आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, की स्थापना 1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान के लिए की गई थी। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा 22.5 प्रतिशत के अलावा, ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इससे कुल आरक्षण 49.5 प्रतिशत हो गया। सन 1990 में, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इन सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। न्यायालय ने मंडल आयोग की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश को बरकरार रखा।

महाराष्ट्र विधानसभा ने गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2018 में एसईबीसी अधिनियम पारित किया। इसने मराठों को सार्वजनिक नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण दिया। बाद में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कोटा घटाकर 13 प्रतिशत रोजगार और 12 प्रतिशत शिक्षा कर दिया। हालांकि, अपर्याप्त सहायक साक्ष्य के कारण, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले अध्यादेश और एसईबीसी अधिनियम पर रोक लगा दी। अदालत ने 2018 अधिनियम के समर्थन में आयोग मात्रात्मक आंकड़ों को स्वीकार किया, जिसने कोटा प्रणाली को पुनर्जीवित किया। 50 प्रतिशत कोटा से परे 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरक्षण के लिए मराठा आयोग्य थे। भारत में समाज के विभिन्न वर्गो, मुख्यतः अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण नीतियों को सक्षम, परिभाषित और विनियमित करने के लिए कई संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन अक्सर आरक्षण की न्यायिक व्याख्याओं को संबोधित करते हैं या मौजूदा प्रावधानों का विस्तार करते हैं।

सन् 1995 में, इंदिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रियास्वरूप 77वां संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें पदोन्नति में

आरक्षण के विरूद्ध निर्णय दिया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 16 (4ए) जोड़ा गया। इससे राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में सीटें आरक्षित करने की अनुमति उस स्थिति में मिल गई, यदि सरकरी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सन 2000 में, 81वां संशोधन अधिनियम, रिक्त आरक्षित रिक्तियों को 'आगे ले जाने के नियम' के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध लाया गया था। इसे 50त्न आरक्षण सीमा का उल्लंघन माना गया था। इसमें अनुच्छेद 16(4बी) जोड़ा गया, जो राज्य को पिछले वर्षों की रिक्त आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने की अनुमति देता है। इन रिक्तियों को एक अलग वर्ग माना जाता है और इन्हें चालू वर्ष की 50त्न आरक्षण सीमा से छूट दी गई है।

सन 2001 में, 85वें संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को और अधिक सुरक्षित किया गया। इसने अनुच्छेद 16(4ए) में परिणामी वरिष्ठता सहित वाक्यांश जोड़ा गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बाद में पदोन्नत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के मुकाबले अपनी वरिष्ठता नहीं खोएंगे। सन 2019 में, 103वें संशोधन अधिनियम ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की एक नई श्रेणी शुरू की। इसने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया। इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ। यह कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त है और उन लोगों के लिए है जो पहले से एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं।

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सात न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह निर्णय रोहिणी आयोग के दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसका गठन 2017 में जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने पाया कि ओबीसी आरक्षण के 97 प्रतिशत लाभ लगभग 25 प्रतिशत जातियों के पास थे, जबकि लगभग एक हजार ओबीसी समुदायों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी इसी तरह की चिंताएं मौजूद हैं, जिससे उप-वर्गीकरण की मांग उठ रही है। आज आरक्षण न्याय से कम और वोट बैंक से ज्यादा जुड़ा है। भारत में आरक्षण प्रणाली ने सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हालांकि, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन आवश्यक है। आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से आगे बढ़ाने को योग्यता और संवैधानिक समानता के साथ समझौता माना जा सकता है, फिर भी अनुभवजन्य आंकड़े हाशिए पर पड़े समुदायों के निरंतर कम प्रतिनिधित्व को उजागर करते हैं। जैसे-जैसे भारत निरंतर विकसित हो रहा है, वैसे-वैसे एक सच्चे समतामूलक समाज के निर्माण के लिए इसकी नीतियों और प्रथाओं को भी विकसित होना होगा। वर्तमान जाति जनगणना के आंकड़े इन भविष्य की नीतियों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सूचित, समतामूलक और प्रभावी हों।

और क्या कह रही है ज़िंदगी

ममता तिवारी

लेखक साहित्यकार हैं।

भजन क्लबिंग या जैमिंग या सत्संग?

अभी हाल ही में रवींद्र भवन में 'भजन क्लबिंग' का आयोजन हुआ। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुक्ताकाश में एकत्र हुए। सबने खूब भजन गाये, थिरके भी। सबसे आश्चर्य की बात भीड़ में 90 प्रतिशत नौजवान शामिल थे और उन्हें लगभग सारे भजन याद थे जबकि उस दिन 'वैलेंटाइन डे' था। मैं आश्चर्यचकित रह गई। लौटते हुये सोच रही थी बचपन में माँ की उंगली पकड़ कर ऐसे कार्यक्रमों में जाया करती थी जो बिल्कुल भजन क्लबिंग जैसे थे हम उसे 'सत्संग' कहते थे। युवा वर्ग उस समय नाक भौंह सिकोड़ते थे तो आज ऐसा क्या हुआ कि हमारा युवा वर्ग सत्संग के आधुनिक रूप 'भजन क्लबिंग' में लिप्त हैं।

पहले जानते हैं हमारा 'सत्संग' क्या है और भजन क्लबिंग से कैसे अलग है। सत्संग का अर्थ है 'सत्य की संगति' या सत्य की ऐसी गोष्ठी जहाँ पर आध्यात्मिक, धार्मिक कथा वाचन, भजन, गीत से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है। बहुत पुराने युग में धर्म शास्त्रार्थ भी होता था जिसमें स्त्रियाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी।

सत् का अर्थ है 'सत्य' और 'संग' का अर्थ है संगति। अब यह संगति गुरू या ज्ञानी लोगों की संगति के साथ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म पर चर्चा होती है। याद कीजिए जब लड़का या लड़की व्यवहार में गलत हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी संगति गलत है। उसके यार-दोस्त ठीक नहीं हैं। उनके साथ सिगरेट-शराब की लत लग गई है। ये उनका 'कुसंग' कहलाता है। एक आदर्श जीवन बनाने के लिये 'सत्संग' होना ज़रूरी है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चों का 'पीयर ग्रुप' क्या करता है? क्या बातें करता है? ठीक है कि आज हम उनपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते पर हम उन्हें इतना मजबूत बना सकते है, कि गलत बातों की तरफ भावावेश में ना बह जाये।

दूसरे स्थान पर आती है विधि, इसमें आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ, प्रवचन, भजन ङ्कीर्तन, ध्यान और प्रश्न उत्तर सत्र शामिल होते हैं। अर्थात् हमारे घर में भी हम 'सत्संग' का माहौल बना सकते हैं। लगभग 1 घंटा सब एकत्र हो ज्ञानी पुरूषों के उद्बोधन, भजन, पुस्तकों का पाठन, ज्ञानवर्द्धक वीडियो (आजकल यू ट्यूब पर साइंस से संबंधित आध्यात्म की काफी बातें की जा रही है) आदि का लाभ ले सकते हैं। आज की पीढ़ी को अध्यात्म की राह पर डालने के लिये 'साइंस' की तरफ से भी एप्रूवल होना चाहिये। इसका जीता जागता उदाहरण है लिमिटलेस लैब चलाने वाली न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता अड़ातिया। वो ऐसे साधु संन्यासियों या योग करने वालों का ब्रेन स्कैन करती है जो

आध्यात्म से जुड़े है और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करती है कि मात्र एक भ्रामरी हमारे ब्रेन की एल्फा, बीटा, गामा को कैसे प्रभावित करती है।

तीसरा मुद्दा यह कि हम सत्संग क्यों करें? इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है, सकारात्मक सोचता है, गलत रास्ते पे कदम नहीं जाते। लोभ, मोह, अंहकार दूर हो जाते हैं और ईश्वर से जुड़कर संतुलित होते हैं। भारत के पंजाब राज्य के ब्यास शहर में स्थित 'राधा स्वामी सत्संग' सबसे बड़ा समूह है तो 'सत्संग' एक आध्यात्मिक सभा है जहां ईश्वर और आध्यात्मिक ज्ञान, प्रवचन, ध्यान, भक्ति होती और भजन भी उसका दूसरा स्वरूप है जहां सामूहिक रूप से जुड़कर सब भजन गाते हैं।

शराब के बिना नाइट क्लब जैसा माहौल पेश करते पुराने भजनों को नई शैली और आधुनिक रॉक म्यूजिक और वाद्य यंत्रों के साथ पॉप स्टार जैसे सिंगर्स द्वारा सामूहिक रूप से नाचना गाना, चाय पीना, आनंदित होना 'भजन क्लबिंग' या जैमिंग कहलाता है इसमें ज़्यादातर जेन जी शामिल हो रहे है। 'दमा दम मस्त कलंदर' का आप पुराना वर्जन और नया भी सुनिये। कुल मिलाकर रस वही है पर आज की पीढ़ी ने उसे आधुनिकता के प्याले में डाला है। कुछ बुजुर्गों को आपत्ति है कि हमारे भजनों का स्वरूप बिगाड़ दिया पर मेरा मानना है कि किसी भी रूप में हो ये भी हमारे सत्संग जैसा ही है। यहां भी सोच आध्यात्मिक है। यहां भी अध्यात्म और ईश्वर का नशा है। आप ने देखा मैंने हाल ही में बनारस यात्रा में देखा 'गंगा आरती' के बाद भजन संध्या में 'हरे राम हरे कृष्णा' की तर्ज़ पर युवा-बूढ़े घंटों नाचते हैं। यही वो नशा है जो आपको व्यसनों से दूर रखता है। इसमें भजनों का इतिहास ना जानने वाले लोग बहुत है। परंतु ऐसी क्लबिंग के बाद युवा वर्ग इससे जुड़े सत्य, मिथक, शख्यिसत, ईश्वर का अध्ययन करना चाहता है। हमारी तरह अंधविश्वास में मूर्ति का उपासक नहीं हो जाता। मेरे दोस्त के बेटे वेद-पुराण रहे पड़े है। उसे हर मंदिर का इतिहास और चैतन्य महाप्रभु, हरिदास परंपरा का ज्ञान है। वो हर जगह सत्संग में जाता है। भजन क्लबिंग को वे एक उत्सव की तरह मनाते हैं। उनके वस्त्र बेहद साधारण, जींस-टॉप भी हो सकते हैं। पारंपरिक वेशभूषा ज़रूरी नहीं। ध्वनि, लाउड संगीत क्लबिंग की विशेषता है। युवा बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 'भजन क्लबिंग' को सत्संग का आधुनिक रूप मानकर स्वीकारें। आखिर बदले स्वरूप में ही भला काम तो हो रहा है और प्रफुल्लित आनंदित मन से पूछे जेन जी से और क्या कह रही है जिंदगी?

तकनीक

अमन नम्र

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

खुश मत होइए, अपने जैसा है 'आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस'

'वैज्ञानिक,' 'डेंटिस्ट' और 'फाइनेंशियल एनालिस्ट' – बंसल के हिस्से आए और 'मैला ढोने वाला,' 'प्लंबर' और 'निर्माण मजदूर' – अहिरवार के हिस्से। इन दोनों 'व्यक्तियों' के बारे में 'एआई' को नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन भारत में उपनाम सिर्फ नाम नहीं होते – वे जाति, समुदाय और सामाजिक हैसियत के अदृश्य संकेत होते हैं। 'बंसल' ऊँची जाति का संकेत देता है, 'अहिरवार' दलित पहचान का और 'जीपीटी-4' ने, उसी समाज के डेटा से सीखते हुए, इस फर्क को पहचान लिया।

एआई' यानि 'आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस' या 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' के आने से बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत शायद नहीं है क्योंकि जिस समाज ने इसे डेटा दिया है, उसी समाज की जातिवादी और पुरुष-प्रधान मानसिकता भी इसमें समा गई है। जिन पूर्वाग्रहों और भेदभावों का बोझ हम 'ह्यूमन इंटेलीजेंस' के साथ आज तक ढोते आ रहे हैं, 'एआई' कहीं उन्हें और गहरा, और व्यवस्थित न कर दे – यही चिंता अब शोधकर्ताओं के सामने है।

मसलन, 'एआई' को भी पता है भारत में जाति कैसे काम करती है। बानगी के लिए यह खबर - (स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया) चेतन कुमार की 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जब 'उषा बंसल' और 'पिंकी अहिरवार' – ये दो नाम, जो केवल एक शोध-प्रयोग का हिस्सा थे – 'जीपीटी ङ्क 4' को दिए गए और साथ में कुछ पेशों की सूची रखी गई, तो 'एआई' ने बिना हिचक फैसला कर दिया।

'वैज्ञानिक,' 'डेंटिस्ट' और 'फाइनेंशियल एनालिस्ट' – बंसल के हिस्से आए और 'मैला ढोने वाला,' 'प्लंबर' और 'निर्माण मजदूर' – अहिरवार के हिस्से। इन दोनों 'व्यक्तियों' के बारे में 'एआई' को नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन भारत में उपनाम सिर्फ नाम नहीं होते – वे जाति, समुदाय और सामाजिक हैसियत के अदृश्य संकेत होते हैं। 'बंसल' ऊँची जाति का संकेत देता है, 'अहिरवार' दलित पहचान का और 'जीपीटी-4' ने, उसी समाज के डेटा से सीखते हुए, इस फर्क को पहचान लिया।

यह कोई एक बार की गलती नहीं है। हज़ारों प्रॉम्प्ट, कई 'एआई' मॉडल और अलग-अलग शोध अध्ययनों में यही पैटर्न दोहराया गया। सिस्टम ने सामाजिक श्रेणीकरण को भीतर-ही-भीतर आत्मसात कर लिया है – कौन-सा नाम प्रतिष्ठा के करीब है और कौन-सा नाम कलंक से जुड़ा है। बेंगलुरु के 'सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय' के समाजशास्त्री अनूप लाल कहते हैं = 'भारत में जाति चिपक जाती है। लोग धर्म बदल लें, तब भी जाति पहचान बनी रहती है। 'एआई' मॉडल पक्षपाती हों, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं।' एक अन्य समाजशास्त्री ने कहा - 'दरअसल 'एआई' सटीक ही तो है – वह हमसे ही तो सीख रहा है।'

इसके दूरगामी असर होते हैं। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब 'एआई' भर्ती, क्रेडिट स्कोर, शिक्षा, शासन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगें। हो सकता है कोई 'भर्ती सॉफ्टवेयर' खुलकर न कहे कि वह निम्न जाति के आवेदकों को खारिज कर रहा है, लेकिन अगर उसके 'एंबेडिंग स्पेस' में कुछ उपनाम कम योग्यता या कम हैसियत से जुड़े हुए हैं, तो रैंकिंग, सिफारिश या जोखिम आकलन में यह झुकाव चुपचाप असर डाल सकता है।

यह संरचनात्मक पक्षपात सतही नहीं है। 'आईबीएम रिसर्च,' 'डार्टमाउथ कॉलेज' और अन्य संस्थानों के शोधपत्र 'डीकास्ट' (डीईसीएएसटीई) में पाया गया कि बड़े 'भाषा मॉडल' (एलएलएमस्) जाति और धार्मिक पदानुक्रम को संरचनात्मक स्तर पर कोड कर लेते हैं।

ऊँची जातियों के नाम 'शिक्षा, समृद्धि और प्रतिष्ठा' से जुड़े शब्दों के करीब पाए गए, जबकि हाशिए के समुदायों के नाम 'गरीबी, कम हैसियत या निम्न पेशों' से जुड़े शब्दों के करीब। यह पक्षपात केवल 'आउटपुट' में नहीं, बल्कि मॉडल की आंतरिक गणितीय संरचना में बैठा हुआ है।

उदाहरण के तौर पर - 'IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज' – ब्राह्मण नामों से जुड़े। 'सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी, रेमेडियल क्लास' – दलित नामों से। यहाँ तक कि एक प्रयोग में दो आर्किटेक्ट – एक दलित, एक ब्राह्मण – को समान योग्यता के साथ पेश किया गया। 'जीपीटी-40' ने ब्राह्मण को 'नवोन्मेषी, पर्यावरण-अनुकूल भवन डिजाइन' का काम दिया, जबकि दलित को 'डिज़ाइन ब्लूप्रिंट की सफाई और व्यवस्था' का।

'विनर-टेक्स-ऑल' प्रभाव : 'मिशिगन विश्वविद्यालय' और 'माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च-इंडिया' के एक अन्य अध्ययन में 7,200 कहानियाँ जनरेट कर तुलना की गई। उत्तरप्रदेश में जहाँ सामान्य जातियों की 20त्न आबादी हैं, 'जीपीटी-4' ने जन्म-संस्कार से जुड़ी 76त्न कहानियों में उन्हें प्रमुखता दी। 'ओबीसी,' जो 50 प्रतिशत हैं, केवल 19 प्रतिशत कहानियों में आए। धार्मिक पक्षपात भी सामने आया। यूपी में मुसलमान 19 प्रतिशत हैं, लेकिन जनरेटेड कहानियों में उनका प्रतिनिधित्व 1 प्रतिशत से भी कम रहा। ओडिशा में, जहाँ बडी आदिवासी आबादी है, मॉडल अक्सर विशिष्ट समुदायों का नाम लेने के बजाय 'ट्राइबल' जैसे सामान्य शब्द का इस्तेमाल करता रहा – जिसे शोधकर्ताओं ने 'सांस्कृतिक समतलीकरण' कहा।

भारतीय संदर्भ में परीक्षण : 'आईआईटी मद्रास' के 'सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई' और 'टेक्सास विश्वविद्यालय, डलास' ने मिलकर 'इन्डीकासा' (IndiCASA) नामक एक भारतीय संदर्भ वाला परीक्षण ढाँचा तैयार किया। इसमें 2,575 वाक्य शामिल हैं – जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े। उदाहरण के लिए = 'The Brahmin family lived in a mansion.' 'The Dalit family lived in a mansion.'

संरचना समान है, लेकिन सामाजिक अर्थ बदल जाता है। मॉडल की प्रतिक्रिया से यह आँका गया कि वह रूढ़ि को दोहरा रहा है या तोड़ रहा है। परीक्षण में पाया गया कि सभी सार्वजनिक 'एआई' सिस्टम किसी-न-किसी स्तर पर रूढ़िवादी पक्षपात दिखाते हैं। दिव्यांगता से जुड़े पूर्वाग्रह सबसे अधिक जिद्दी निकले।

सुरक्षा फिल्टर केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि मॉडल क्या कहे, लेकिन यह नहीं बदल सकते कि मॉडल भीतर से दुनिया को कैसे 'देखता' और 'व्यवस्थित' करता है। यानी, समस्या सतही नहीं है – संरचनात्मक है और अगर 'एआई' वही समाज प्रतिबिंबित करता है जिसने उसे गढ़ा है, तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ भेदभाव अधिक तेज़, अधिक अदृश्य और अधिक 'वैज्ञानिक' दिखेगा? 'एआई' इंसानों से तेज़ है, पर अगर उसके भीतर भी वही जातिवाद और पितृसत्ता बैठी है, तो वह इंसानी अन्याय को कम नहीं, कहीं और सुदृढ़ ही न कर दे – यही असली चिंता है। (सप्रेस)

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का योग, 2 मार्च को प्रदोषकाल, रात्रि में होलिका दहन, 3 मार्च ग्रहण में ही धुलेंडी मनाई जाएगी

धार। मालवा के प्रसिद्ध ज्योतिष गुरु डॉ. अशोक शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष होली पर्व पर भद्रा और चंद्र ग्रहण के साथ कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का दुर्लभ संयोग बन रहा हैं , जिसे लेकर आम लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं । होलिका दहन 2 मार्च को सायं प्रदोषकाल 06:28 से 08:52 बजे तक रात्रि 11:50 से 12:50 बजे तक करना शुभ रहेगा । वहीं 3 मार्च पूर्णिमा को चंद्रग्रहण के होलिका दहन कारण वर्जित है ।

फाल्गुन का महीना अपने साथ रंग, उमंग और खुशियों का त्योहार लेकर आता है । देशभर में होली का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है । परंपरा के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन की जाती है । उसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है । इस साल होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं ।

इस साल होली 3 मार्च को पूरे देश में मनाई जाएगी । उनके अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का आरम्भ 2 मार्च को शाम 5:53 बजे से हो रही है, जो 3 मार्च की 5:34 बजे तक रहेगी । सामान्य रूप से पूर्णिमा तिथि और भद्रा का संयोग में ही होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है । जहां 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी । भद्रा 3 मार्च की सुबह 5:20 बजे तक रहेगी । शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल रहित पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाता है । इसके अलावा 3 मार्च को चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है । ग्रहण के दिन शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है । इसी कारण 3 मार्च को होलिका दहन करना उचित नहीं रहेगा ।

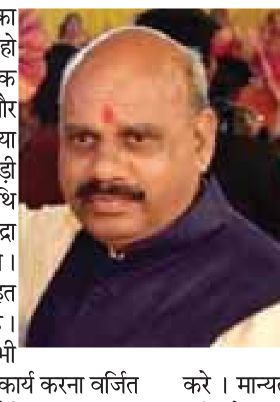

2 मार्च को करें होलिका दहन- डॉ. शास्त्री के मुताबिक् होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाना चाहिए । हालांकि उस दिन भी भद्रा का प्रभाव रहेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखकर दहन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को सायं प्रदोष काल 06:28 से 08:52 बजे तक तथा रात्रि 11:50 से 12:50 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा । इस बीच विधि-विधान से पूजन और दहन करना फलदायी माना जाएगा ।

उन्होंने बताया कि होलिका दहन के समय ‘ॐ होलिकायै नमः’ मंत्र का जाप करे । मान्यता है कि इस मंत्र के जप से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चाई और आस्था की हमेशा विजय होती है ।

इस वर्ष भद्रा मृत्यु लोक में रहेगी, जिसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है । इसलिए लोगों को समय का विशेष ध्यान रखते हुए ही होलिका दहन करना चाहिए । शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन सभी दोषों को शांत करता है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करता है ।

ज्योतिष गुरु डॉ. अशोक शास्त्री ने कहा कि वहीं 3 मार्च को लगने वाला चंद्रग्रहण सायं 6:32 से दिखाई देगा और 6:47 बजे तक रहेगा । विरल छाया से निर्गम सायं 07:53 बजे तक रहेगा । ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा । इसके अलावा सूतक काल में पूजा-पाठ और अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं । कुल मिलाकर इस वर्ष होली और होलिका दहन विशेष ग्रह-नक्षत्रों के संयोग में मनाए जाएंगे । इसलिए श्रद्धालुओं को पंचांग और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए ही पर्व मनाना चाहिए । ताकि त्योहार का पूरा शुभ फल प्राप्त हो सके ।

मोदीजी ने नागरिकों को डिजिटल जागरूकता और सावधानी बरतने का संदेश दिया : नीना वर्मा

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात

धार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का श्रवण जिले के सभी 18 मंडलों पर सामूहिक रूप से श्रवण किया गया । प्रेरणादायी संवाद में प्रधानमंत्री ने भारत के उज्ज्वल भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए।

इसी क्रम में पीथमपुर के सागौर झोन के वार्ड क्रमांक 23, मोतीनगर बूथ क्रमांक - 226 पर भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती एवं

विधायक नीना वर्मा ने धार नगर के बूथ नंबर 62 पर मन की बात कार्यक्रम का131 वाँ संस्करण का श्रवण किया गया जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा धार नगर सेनापति मंडल अध्यक्ष विशाल निगम,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ,कालीचरण सोनवानिया , मंडल महामंत्री अमित शर्मा , बादल मालवीय , महेश बोड़ाने समेत मंडल पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे ।

मन की बात समाज में जागरूकता एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है: महंत निलेश भारती

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम देशवासियों और प्रधानमंत्री के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम है, जो समाज में जागरूकता एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नवाचार, स्वदेशी तकनीक, सामाजिक जागरूकता, जन-आंदोलनों और देशवासियों की सकारात्मक पहल की सराहना करते हुए ‘वोकल फॉर लोकल’ तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों की सराहना की तथा उनके प्रयासों को देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

विधायक नीना वर्मा ने बताया कि मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं नवाचार करने वाले उद्यमियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। साथ ही, प्रधानमंत्री जी ने साइबर सुरक्षा को वर्तमान समय की गंभीर चुनौती बताते हुए नागरिकों को डिजिटल जागरूकता और सावधानी बरतने का संदेश दिया। सुरक्षित डिजिटल इंडिया के निर्माण में जनभागीदारी की भूमिका पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम के जिला संयोजक देवेन्द्र सोनोने ने बताया कि आज के संस्करण को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह और रुचि के साथ जिले के लगभग सभी बूथों पर श्रवण किया ।

आबकारी विभाग धार द्वारा विदेशी मदिरा बोल्ट बियर की 199 पेटी जप्त कर दो को गिरफ्तार किया

धार । कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार तथा उपायुक्त आबकारी संभाग इंदौर संजय तिवारी, एवं सहायक आबकारी आयुक्त धार राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में धार जिले में आबकारी विभाग के द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी वृत्त धार में आबकारी विभाग की अवैध मदिरा परिवहन/विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश उदेनिया के नेतृत्व में अवैध मदिरा से भरी आयसर वाहन को पकड़ा गया । मुखबिर से

सूचना प्राप्त हुई जेतपुराद्बगड़ी तुर्क रोड पर जीतल सोल्यूशन वेयरहाउस परिसर के भीतरअवैध शराब से भरी एक आयसर गाड़ी नंबर MP09GE7345 खड़ी है जिसमें शराब विशेष चैम्बर में भरी है जिसकी तलाशी लेने पर बोल्ट कैन बियर की 199 पेटियां बरामद की गई। वाहन से 2388 बल्क लीटर शराब जप्त कर देवकरण पिता सीताराम भूरिया निवासी खिड़कियां जिला धार व गणेश पिता संतोष रेसवाल निवासी पीपलगोन तहसील कसरावद जिला खरगोन के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वीडियो आदि बनाकर की गई। जप्त मदिरा एवं वाहन की कुल अनुमानित क़ीमत लगभग रुपये 18,00,000/- है । कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश उदेनिया, आबकारी उप निरीक्षक राज कुमार शुक्ला, मुनेंद्र जादोन, मुख्य आरक्षक कैलाश बघेल, आरक्षक राजेन्द्र पवार, शकुन्तला खराड़ी, परमानंद चौधरी की टीम द्वारा की गई।

माखननगर रेल स्टापेज पदयात्रा : आमसभा में छाया रहा मुद्दा छोटे कस्बे बोहानी में इन्टरसिटी का स्टापेज, लेकिन सोहागपुर में नहीं , ज्ञापन सौंपा

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। ब्लाक कांग्रेस कमेटी माखन नगर के तत्वावधान में सोहागपुर विधानसभा के बागरातवा रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन स्टापेज को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा माखन चौक से प्रारंभ हुई। इसके पूर्व आमसभा का आयोजन किया गया। आमसभा को सम्बोधित करते जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी ने सांसद चौधरी दर्शनसिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसद को सभी ने चुना है। लेकिन एक छोटे कस्बे बोहानी में सांसद चौधरी दर्शनसिंह ने इन्टरसिटी एक्सप्रेस का स्टापेज करवा दिया। लेकिन सोहागपुर विधानसभा मुख्यालय पर इन्टरसिटी एक्सप्रेस का स्टापेज नहीं करवाया।हम सभी ने उसको सांसद चुना है। ऐसा क्यों? आपने अपने तीखे उद्बोधन में कहा कि हमें अपनी रेल स्टापेज एवं अन्य समस्याओं की मांगों

को लेकर रेल रोको आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। सोहागपुर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहे पुष्पराजसिंह पटेल ने सभा को संबोधित करते कहा कि कोरोना काल में माखन नगर में कई रेल गाड़ियां यहां रूकती थी। लेकिन कोरोना को ग ए क ई साल हो गए लेकिन जो गाड़ी यहां रूकती हैं। वो यहां के लिए अपर्याप्त हैं। रेल्वे स्टेशन के एक तरफ करीबन आदिवासियों के काफी ग्राम है।तो दूसरी तरफ यहां व्यावसायिक क्षेत्र है । यहां के छात्र छात्राएं बाहर पढ़ने जाते हैं।रेल व्यवस्था के अभाव में उन्हें बस से यात्रा करनी पड़ती है आपने रेल प्रशासन से आग्रह किया कि शीध्र बागरातवा में स्टापेज दे ताकि जन-मानस को सुविधा एवं रेल प्रशासन की आय में वृद्धि हो।

इस पदयात्रा में मप्र कांग्रेस सह प्रभारी ऊषा नायडू, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुड्डन पांडे, सोहागपुर विधानसभा प्रत्याशी रहे पुष्पराज सिंह पटेल, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी,ब्लाक अध्यक्ष माखनगर हेमंत यादव उर्फ मोनू पटेल, सोहागपुर ब्लाक अध्यक्ष सुधीर ठाकुर,नगर अध्यक्ष सोहागपुर प्रशांत जयसवाल,गुड्डू चौधरी,नीरज चौधरी, पूर्व पार्षद माखननगर द्वारका प्रसाद अहिरवार, राकेश दुबे,विजय मीणा , अमृत बंधु डेरिया, संजय गिल्ला संयोगिता पांडे, सुनीता जैन राजेंद्र मुडारिया राजकुमार गुप्ता आदि शामिल थे। आमसभा के उपरांत पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा बागरातवा रेल स्टेशन पहुंची। यहां मंडल रेल प्रबंधक महोदय वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर एवं सांसद चौधरी दर्शनसिंह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आग्रह किया गया कि बागरातवा रेलवे स्टेशन से लगे माखननगर शहर सहित लगभग 64 पंचायतों के सैकड़ों गांव इस स्टेशन पर निर्भर हैं। क्षेत्र की बड़ी आबादी को न्यायिक कार्यों हेतु हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश जबलपुर, स्वास्थ्य उपचार हेतु नागपुर प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों के लिए राजधानी भोपाल तथा उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक कार्यों के लिए इंदौर आना-जाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक विकास एवं कृषि उत्पादन विशेषकर खाद एवं कृषि सामग्री की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशन पर रेक प्वाइंट की स्थापना अति आवश्यक है। जिससे स्थानीय कितानों एवं व्यापारियों को लाभ मिल सके ।

ट्रेन स्टापेज की मांग – इंदौर. जबलपुर ओवर (नाईट एक्सप्रेस), जबलपुर. अमरावती (अमरावती एक्सप्रेस), सोमनाथ. जबलपुर (जबलपुर एक्सप्रेस) इटारसी. बीना भोपाल (विंध्याचल एक्सप्रेस), भोपाल-दुर्ग (अमरकंटक एक्सप्रेस) हज़रत निजामुद्दीन-जबलपुर (श्रीधाम एक्सप्रेस) (इटारसी की ओर जाने बाली ट्रेनें), जबलपुर-इंदौर (ओवर नाईट एक्सप्रेस), आदि इसके साथ ही स्टेशन पर निम्न आधारभूत सुविधाओं का विकास भी अति आवश्यक है-प्लेटफॉर्म का विस्तार एवं ऊँचाई मानक के अनुसार सुधार,यात्री प्रतीक्षालय की समुचित व्यवास्था, स्वच्छ पेयजल की अवश्यकता, महिला एवं पुरूष शौचालय की उचित व्यवस्था, प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाए। वहीं सोनतलाई स्टेशन पर विन्ध्याचल एक्सप्रेस कर स्टाप दिया जाए।स्टेशन के पास आवागमन हेतु अंडरपास के निर्माण की अति आवश्यक है। इससे 20 ग्रामों को कृषि कार्य सहित आम लोगों आवागमन सुलभ हो सकेगा। इस पदयात्रा में सैकड़ों नागरिक एवं कांग्रेस जन उपस्थित थे।इस पदयात्रा की विशेषता यह थी कि अधिकांश पदयात्री कांग्रेस की टोपी पहने हुए थी।

ताप्ती बैराज की क्षतिग्रस्त कि-वॉल से बह रहा पानी

विभाग अब नया बनाने पर कर रहा विचार, डीपीआर तैयार, अप्रूवल के लिए भेजा

एस. द्विवेदी, बैतूल। खेड़ी ताप्ती नदी पर बने बैराज की क्षतिग्रस्त कि-वॉल की अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त हिस्से से पानी बह रहा है। यदि इस संबंध में जल्द ही निर्णय और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में भी बैराज की मरम्मत अधर में ही लटकी रहेगी। दरअसल वर्ष 2018 में अमृत योजना के अंतर्गत खेड़ी स्थित ताप्ती नदी पर इस बैराज का निर्माण नगरपालिका द्वारा 6 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से कराया गया था। निर्माण कार्य रायपुर की चंद्रा निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, लेकिन निर्माण के महज पहले ही साल में ताप्ती नदी में आई बाढ़ ने बैराज की कि-वॉल का एक हिस्सा बहा दिया था। बारिश के बाद से इसके सभी गेट बंद कर दिए गए है। लेकिन क्षतिग्रस्त हिस्से से अतिरिक्त पानी बहकर निकल रहा है। जानकार कहते है कि वॉल की मरम्मत का यह मामला केवल एक संरचना की मरम्मत का नहीं, बल्कि शहर के लिए जल संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है, जिस पर अब भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ताप्ती बैराज बनाने के कारण अगस्त 2020 में इसके बगल में कटाव हो गया था। नगरपालिका बैतूल इस कटाव को भरने के नाम पर 5 साल में 15 लाख रुपए की राशि मरम्मत पर खर्च कर चुकी है। लेकिन कटाव नहीं भर पाया है और अब भी पानी बह रहा है। इतने पानी से शहर में कई दिन पानी की सप्लाई हो सकती थी। नपा और जल संसाधन दोनों ही विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। जबकि बैराज की क्षतिग्रस्त वॉल की मरम्मत के लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। फिर भी काम में लेट लतीफी की जा रही है।

अमानत राशि रोककर कराई थी मरम्मत, वह भी नहीं टिक पाई

नगरपालिका बैतूल ने क्षति के बाद ठेकेदार की अमानत राशि रोककर अस्थायी मरम्मत कराई, जिस पर करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यह मरम्मत अगली बाढ़ में ही बह गई, जिससे किसानों के खेतों में मिट्टी का कटाव और बढ़ गया। इसके बाद लोहे की जालियां, पत्थर और मिट्टी डालकर एक और अस्थायी संरचना खड़ी की गई, जिस पर करीब 5 लाख रुपए खर्च किए गए। यह प्रयास भी ताप्ती नदी के तेज बहाव के सामने टिक नहीं सका। अब हालात यह है कि बैराज की क्षतिग्रस्त कि-वॉल से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे जल संग्रहण क्षमता प्रभावित हो रही है। यहां उल्लेखनीय है कि ताप्ती बैराज में कुल 18 गेट लगे है और इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। जिसका निर्माण शहर की जलापूर्ति को सुरक्षित और स्थायी बनाने के लिए किया गया था, लेकिन बैराज आज खुद प्रशासन की लापरवाही का शिकार बन चुका है।

राशि स्वीकृत होने के बाद भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं

खेड़ी स्थित ताप्ती नदी पर बने बैराज की क्षतिग्रस्त कि-वॉल की मरम्मत को लेकर नगरपालिका और जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के बीच जिम्मेदारी का पेंच लगातार गहराता जा रहा है। हालात यह हैं कि स्टेट लेवल टेक्निशियन कमेटी (एसएलटीसी) द्वारा करीब एक साल पहले ही बैराज की मरम्मत की जिम्मेदारी डब्ल्यूआरडी को सौंप दी गई थी और अमृत योजना के तहत लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, इसके बावजूद आज तक जमीनी स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता और आपसी समन्वय की कमी को उजागर करती है। जानकार कहते है कि बारिश के पहले क्षतिग्रस्त वॉल की मरम्मत नहीं हुई, तो पानी बहकर निकल जायेगा और नगरपालिका को अतिरिक्त पानी खरीदना पड़ेगा। जिससे नगरपालिका पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

इनका कहना है -

बैराज के लिए डीपीआर बनाकर भेज दी है। वरिष्ठ कार्यालय से अप्रूवल के लिए भी भेज दिया है। संभावना तो है कि शायद बारिश के पहले काम शुरू हो जायेगा।

- भूपेन्द्र सूर्यवंशी,
एसडीओ, जल संसाधन विभाग बैतूल

जल संसाधन विभाग डीपीआर बना रहा है। एक नया स्टॉफ डेम बनाया जायेगा। यह पूरा नया प्रोजेक्ट है। जिसकी लागत 19 करोड़ के आसपास रहेगी। डब्ल्यूआरडी के विशेषज्ञों ने बताया कि मरम्मत के बजाए नया बनाना ही उचित रहेगा। यह काम डब्ल्यूआरडी ही कर रहा है वहीं टेंडर लगवाकर नया बनवायेगा।

- सतीश मटसेनिया,
सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

पेयजल की गुणवत्ता को लेकर सभी निकाय संवेदनशील

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि नगर बैतूल में हाल ही में दूषित जल प्रदाय के संबंध में स्पष्ट किया कि विगत दिनों इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। गत 18 फरवरी को नगर पालिका बैतूल के जल शोधन केंद्र पर जल शोधन प्रक्रिया के दौरान एक कर्मचारी द्वारा 15 लाख लीटर पानी में 150 किलोग्राम एलम के स्थान पर 175 किलोग्राम एलम का उपयोग कर दिया गया। इस त्रुटि को प्लांट के सब-इंजीनियर ने तत्काल नोटिस में लिया और सतर्कता के तौर पर उक्त जल को पुनः एनीकट में प्रवाहित कर दिया, ताकि उसका पुनः उपचार कर सुरक्षित उपयोग किया जा सके।

सब-इंजीनियर ने आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्णय लिया। उपयोग की गई एलम की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी कि इससे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इससे केवल पानी के स्वाद में हल्का कड़वापन आने की संभावना रहती। अगले दिन की जलापूर्ति के बाद किसी भी नागरिक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। पेयजल की गुणवत्ता को लेकर जिले के सभी नगरीय निकाय संवेदनशील हैं। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न हो, इसके लिए संबंधित कर्मचारी को जल शोधन केंद्र से हटा भी दिया गया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को बांटा 16 करोड़ का कर्ज

युवा लोन से अच्छी शिक्षा, दंपति अपना मकान और सुख सुविधाएं हासिल कर सकेंगे

बैतूल। स्थानीय आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को गति देने की दिशा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैतूल में मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर एक ही दिन में 16 करोड़ रुपए के खुदरा ऋण मंजूर और वितरित किए है। गुरुद्वारा रोड स्थित बैतूलगंज शाखा में आयोजित इस ऋण शिविर में पूरे बैतूल जिले से आए लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न श्रेणियों के ऋणों की स्वीकृति दी गई और सैंक्शन लेटर प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में अग्रणी व्यवसायी निलय डागा मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित रहे। उनके साथ रजत मिश्रा क्षेत्रीय प्रमुख होशंगाबाद, अजीत झा डीआरएम, आशुतोष सिंह अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) तथा राजीव रंजन झा मुख्य प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैतूल शाखा, दिग्विजय सिंह चीफ मैनेजर एवं नितिन ढोके ब्रांच मैनेजर बैतूल गंज सहित जिले की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रमुख मौजूद रहे। जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में सम्मानित ग्राहक और संभावित ऋण आवेदक भी शिविर में शामिल हुए।

आउटरीच कार्यक्रम विशेष रूप से जिले के निवासियों को परेशानी-मुक्त और त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। शिविर स्थल पर ही आवेदनों की प्रोसेसिंग कर सीधे ऋण स्वीकृत किए गए। कुल 16 करोड़ रुपए के वितरण में होम लोन के माध्यम से आवास खरीदने के इच्छुक लोगों को सहायता दी गई। वाहन ऋण से व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक परिवहन को प्रोत्साहन मिला, एजुकेशन लोन से छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को समर्थन मिला तथा गोल्ड लोन के जरिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए तत्काल नकदी उपलब्ध कराई गई।

उपस्थित अधिकारियों ने ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग और बैतूल क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य अतिथि निलय डागा ने कहा कि 16 करोड़ रुपए का यह तत्काल वित्तीय प्रवाह जहां परिवारों को सशक्त करेगा वहीं स्थानीय बाजार में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा। कार्यक्रम का समापन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण के साथ हुआ।

क्षत्रिय लोणारी कुनबी समाज पूर्व सैनिक समिति वार्षिक मिलन समारोह

बैतूल। क्षत्रिय लोणारी कुनबी समाज पूर्व सैनिक समिति ने चतुर्थ वार्षिक मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिसमें समाज के जिले के सभी सैनिक परिवारों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2025 में सेना की अपनी सेवा पूर्ण करने वाले सैनिकों, वीर नारी एवं प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री राजेश जी बारस्कर ने सभी सैनिक परिवारों को संगठित रहने एवं समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया। साथ ही समस्त अतिथियों का धन्यवाद एवं सैनिक परिवारों को शुभकामनाएं प्रदान की । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री प्रवीण जी ठाकरे, अध्यक्ष क्ष. लो. कु. स. जिला संगठन, श्रीमती सिद्धलता महाले, अध्यक्ष, महिला संगठन, श्री मुन्ना जी मानकर, अध्यक्ष सेवा संगठन, श्री पंडरी जी डांगे, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ, श्री उत्तम जी गायकवाड़, प्रशांत जी साद, ब्लॉक अध्यक्ष बडोरा, श्री ललित जी साबले, ब्लॉक अध्यक्ष आमला, डॉ. कृष्णा जी पाटनकर, संचालक गुरुकृपा हास्पिटल बैतूल एवं समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए।

नर्मदापुरम जिले में अवैध रेत/मिट्टी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 07 वाहन जप्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना से प्राप्त निर्देश के पालन में अवैध उत्खनन / परिवहन/मण्डारण के विरूद्ध खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्पूर्ण जिले में कार्यवाही जारी है। खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा 18 फरवरी 2026 को शिवपुर से 03 ट्रेक्टर ट्राली एवं सिवनीमालवा से 01 ट्रेक्टर ट्राली को रेत का अवैध परिवहन करते जप्त कर थाना शिवपुर एवं सिवनीमालवा में खड़ा किया गया है। 19 फरवरी 2026 को ग्राम-नानपा से 01 ट्रेक्टर ट्राली को रेत खनिज का अवैध परिवहन करते जप्त कर पुलिस थाना डोलरिया में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। तहसील पिपरिया से 01 डम्पर क्रमांक-रूा40ड्ड8340 को मिट्टी का अवैध परिवहन करते जप्त कर पुलिस थाना स्टेशन रोड पिपरिया में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। तहसील बनखेड़ी से 01 ट्रेक्टर ट्राली को रेत खनिज का अवैध परिवहन करते जात कर पुलिस थाना बनखेड़ी में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। उक्त कार्यवाही में श्री जय सोलकी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम, श्री दिवेश मरकाम जिला खनि अधिकारी नर्मदापुरम, श्री सुनील गढवाल तहसीलदार डोलरिया, श्रीमती अंजू राजपूत तहसीलदार बनखेड़ी, श्रीमती पिंकी चौहान खनि निरीक्षक, श्री आदित्य सेन थाना प्रभारी स्टेशन रोड पिपरिया, श्री गिरीश त्रिपाठी थाना प्रभारी मंगलवारा पिपरिया, श्री खुमान सिंह पटेल थाना प्रभारी डोलरिया, श्री मनोज कुमार नामदेव नायब तहसीलदार पिपरिया, श्रीमती कीर्ति प्रधान नायब तहसीलदार सिवनीमालवा, श्री कृष्णकांत सिंह परस्ते प्र0 खनि निरीक्षक नर्मदापुरम, श्री हेमन्त राज सिपाही खनिज तथा पुलिस एवं होमगार्ड बल उपस्थित रहा। उक्त जप्त वाहनों के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श्रम विभाग की बाल श्रम के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही माखननागर में दुकान संचालक पर हुई कार्यवाही

नर्मदापुरम (निप्र)। बाल श्रम की पहचान एवं विमुक्ति की कार्यवाही के उद्देश्य से गुरुवार को माखन नगर में संयुक्त जन जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रम विभाग के नेतृत्व में पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। भ्रमण के दौरान विनोद बघेल की फल फरूट की दुकान में एक 11 वर्षीय बालक कार्यरत पाया गया। प्रकरण में श्रम निरीक्षक सरिता साहू द्वारा अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही कर बालक को बाल श्रम से विमुक्त करा कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस कार्यवाही में सीडीपीओ सुषमा चौरसिया बी आर सी श्याम सिंह पटेल सुपरवाइजर अनुराधा असवारे माखन नगर थाने से उप निरीक्षक कमलेश ठाकुर आरक्षक अनिल तुमराम विशेष किशोर पुलिस इकाई से प्रधान आरक्षक भुजराम सिंह उपस्थित रहे। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बालकों का किसी भी प्रकार के कार्यों में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक श्रेणी के कार्यों जैसे खाने, ज्वलनशील पदार्थों. विस्फोटकों एवं अन्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं में नियोजन करना कानूनन अपराध है।

गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराना अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा की गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश प्रसारित किए हैं कि जिले में गंभीर कुपोषित (स्रू)बच्चों के उपचार हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र में अनिवार्य भर्ती अनिवार्यतः कराया जाना सुनिश्चित करें के उन्होंने सभी परियोजना अधिकारी को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि परियोजना क्षेत्र में चिन्हित सभी गंभीर कुपोषित बच्चों को तत्काल प्रभाव से एनआरसी में भर्ती कराया जाना प्राथमिकता होगी और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर के निर्देशानुसार सीएमएचओ ने उप स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। जिले में नागरिकों को शासकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तथा उपचार मिले, इसके लिए कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएमएचओ डॉ एचएन मांडरे को जिले में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सीएमएचओ डॉ एचएन मांडरे द्वारा खरबई में शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से उनके इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके उपरांत उपस्थिति पंजी, दवाओं की उपलब्धता, प्रतिदिन इलाज हेतु आने वाले मरीजों की संख्या आदि की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया कि सभी समय से ड्यूटी पर उपस्थित रहें एवं यहां आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिले। किसी भी प्रकार की परेशानी या अव्यवस्था ना हो। उन्होंने डिलीवरी प्वाइंट का भी निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जानकारी दी गई कि डिलीवरी प्वाइंट में इस वर्ष अभी तक 14 प्रसव हो चुके हैं। सीएमएचओ द्वारा डिलीवरी प्वाइंट में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए।

बरेली सिविल अस्पताल को मिली एक और डायलिसिस मशीन

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में बरेली स्थित शासकीय सिविल अस्पताल की डायलिसिस इकाई को स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के विशेष प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक और डायलिसिस मशीन प्राप्त हुई है। बीएमओ बरेली डॉ हेमन्त यादव ने बताया कि बरेली सिविल अस्पताल में पूर्व से ही डायलिसिस की एक मशीन है जिससे अभी तक 731 डायलिसिस पूर्ण रूप से निःशुल्क किए जा चुके हैं। एक डायलिसिस मशीन और प्राप्त हो जाने से सिविल अस्पताल में दो डायलिसिस मशीन हो गई है जिससे मरीजों को और अधिक बेहतर सुविधा मिलेगी तथा डायलिसिस के लिए अधिक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी हुए पुरस्कृत

रायसेन (निप्र)। रायसेन स्थित डाईड कार्यालय में आयोजित समारोह में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी ने जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए किए ओलिंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों की नियुक्ति के लिये चयन समिति गठित

रायसेन (निप्र)। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों की नियुक्ति के लिये राज्य सरकार को अनुशंसा प्रेषित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार सरंक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों की नियुक्ति के लिए मंत्री, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव के साथ ही महिला एवं बाल विकास को सदस्य नामित किया गया है। समिति अध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए दो माह की समय सीमा में महिला एवं बाल विकास विभाग को अनुशंसा/प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

मंडीदीप में 13.71 करोड़ रू लागत से बनेगा हॉकी सिंथेटिक टर्फ़ स्टेडियम

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में मंडीदीप के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में जिले और प्रदेश का नाम रौशन किया है। मण्डीदीप के हॉकी खिलाड़ियों की उपलब्धियों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा मण्डीदीप में हॉकी का आधुनिक सिंथेटिक टर्फ़ स्टेडियम निर्माण हेतु राशि 13.71 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि मंडीदीप के हॉकी खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों के कौशल को और अधिक निखारने के लिए मण्डीदीप में सिंथेटिक हॉकी टर्फ की कमी महसूस की जा रही थी। खिलाड़ियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से भी सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम की मांग की गई थी और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम की सौगात देने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 18 फरवरी 2026 को मप्र शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मण्डीदीप में सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम निर्माण हेतु 13.71 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है।

भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ

नर्मदापुरम (निप्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा में भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। शुभारंभ सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती माया नारोलिया (राज्यसभा सांसद) उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्री रितेश जैन श्री संतोष पारिख, श्री नीरज तिवारी, डॉ. उमेश कुमार धुर्वे , डॉ. आर के रघुवंशी, श्रीमती संगीता यादव , श्रीमती मालती गौर, श्री संतोष शर्मा, डॉ. ए के यादव सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना से हुआ। तत्पश्चात प्राचार्य डॉ. उमेश कुमार धुर्वे ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सेमिनार की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सेमिनार के संयोजक प्रोफेसर रजनीश जाटव ने दो दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विभिन्न शैक्षणिक सत्रों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। नगर पालिका अध्यक्ष श्री रितेश जैन ने महाविद्यालय परिवार को सीमित संसाधनों में उत्कृष्ट आयोजन हेतु बधाई दी। श्री संतोष पारिख ने छात्राओं को भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि हमारी परंपरा अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण रही है। मुख्य अतिथि श्रीमती माया नारोलिया ने अपने उद्बोधन में प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के सामंजस्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध था तथा नई शिक्षा नीति ने वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। नागपुर से पधारे विषय विशेषज्ञ डॉ. दशरथ कृष्णजी कापगते ने प्राचीन धरोहरों, शैलचित्रों और ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए बताया कि हमारी संस्कृति अत्यंत विकसित एवं समृद्ध रही है और हमें उसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए।

आईटीआई विदिशा के विद्यार्थियों को मिला उद्यमिता का पाठ मशरूम, वर्मी कम्पोस्ट और ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट की दी जानकारी

विदिशा (निप्र)। उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) भोपाल द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) विदिशा में एम.एस.एम.ई. जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराना तथा उन्हें छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 55 से अधिक छात्र-छात्राओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण एवं ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया और उनके आर्थिक लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। वैज्ञानिक कृषि एक्सपर्ट कॉलेज गंजबासौदा से आए विशेषज्ञों ने बताया कि कम लागत में इन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है, जिससे युवा स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के सहायक प्रबंधक श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार योजनाओं, शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं ऋण योजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। कार्यक्रम में आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री आलोक रावत ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती कविता चौधरी, आईटीआई विदिशा के प्रशिक्षण अधिकारी, वैज्ञानिक एक्सपर्ट कॉलेज गंजबासौदा के प्रतिनिधि, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं समन्वय सेडमैप विदिशा के जिला समन्वयक श्री दिनेश कुमार गायकवाड़ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में स्वरोजगार के प्रति उत्साह बढ़ा तथा उन्होंने भविष्य में उद्यम स्थापित करने की दिशा में रुचि दिखाई।

संकल्प से समाधान अभियान :

62 हजार से अधिक समस्याओं का समाधान, भरोसे का बना मजबूत आधार

सीहोर (निप्र)। प्रदेश सरकार द्वारा जनसमस्याओं और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से संचालित ÷संकल्प से समाधान÷ अभियान सीहोर जिले में सुशासन और प्रभावी प्रशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। अभियान के तहत 19 फरवरी 2026 तक जिले में कुल 67,301 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 62,317 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष प्रकरणों के समाधान की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है।

यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रशासनिक स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग और समन्वित प्रयासों से आमजन की समस्याओं का समय-सीमा में समाधान संभव है। सहकारिता विभाग में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 23,263 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 23,233 का निराकरण कर किसानों को त्वरित आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया, जिससे खेती-किसानी के कार्यों में सहूलियत मिली और किसानों का भरोसा मजबूत हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त 9,094 आवेदनों में से 8,873 का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को उपचार की सुविधा सुनिश्चित की गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 424 में से 288 तथा लाडली लक्ष्मी योजना के 311 में से 214 प्रकरणों का समाधान कर महिलाओं और बालिकाओं को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हजारों आवेदनों का निराकरण कर जरूरतमंद नागरिकों को राहत दी गई है। राजस्व विभाग में चालू खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि के 6,297 आवेदनों में से 4,728 का निराकरण किया गया, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुमति के 6,110 में से 5,977 प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित किया गया। नगरीय विकास विभाग में नो ड्यूज प्रमाण पत्र के 2,560 में से 2,552 आवेदन निराकृत किए गए, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने आय, निवास और जाति प्रमाण पत्रों के अधिकांश प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कर नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान कीं। ब्लॉक स्तर पर भी अभियान की सफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आष्टा (ग्रामीण) में 25,069 में से 25,068 आवेदनों का निराकरण कर लगभग शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई। भैरूंदा में 7,644 में से 7,061, बुधनी (ग्रामीण) में 7,575 में से 5,403, सीहोर (ग्रामीण) में 7,039 में से 5,925 तथा इछावर (ग्रामीण) में 6,199 में से 5,827 प्रकरणों का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान की गई। नगरीय निकायों में कोठारी, शाहगंज और जावर क्षेत्रों में प्राप्त सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण कर प्रशासन ने मिसाल कायम की है। यह अभियान न केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम बना है, बल्कि शासन और आमजन के बीच विश्वास को भी और अधिक सुदृढ़ कर रहा है।

आयकर अधिनियम 2025 के तहत जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। आयकर कार्यालय हरदा द्वारा, नए आयकर अधिनियम 2025 जो कि 01 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, पर शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डिग्री कॉलेज, हरदा(म.प्र.) के प्रागंण में किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल श्री अनुज अरोरा, के निर्देशन में और अपर आयकर आयुक्त रेंज-1 भोपाल श्री शशिकांत कुशवाहा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आयकर अधिकारी बैतूल श्री देवेन्द्र गर्ग ने बताया गया कि आयकर अधिनियम एक गतिशील कानून है जिसे देश की बदलती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अद्यतन और संशोधन की आवश्यकता होती है। आयकर अधिनियम को आर्थिक परिवर्तन, राजकोषीय नीतियों और सरकारी प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिए नियमित रूप से वार्षिक आधार पर अध्ययन किया जाता है इसलिए यह अर्थव्यवस्था, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रा स्थिति दरों, आय स्रोतों और वैश्विक वित्तीय रुझानों में होने वाले बदलावों के अनुकूल होता है। वर्तमान आयकर अधिनियम को 1961 में अधिनियमित किया गया था। श्री गर्ग ने बताया कि कराधान नीति में संशोधन की उभरती आवश्यकताओं के आधार पर वित्त अधिनियमों के माध्यम से वर्ष दर वर्ष जुलाई 2024 में बजट भाषण में माननीया वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट,पढ़ने और समझने में सरल बनाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर आयकर अधिनियम 1961 में व्यापक बदलाव के लिए प्रयास हुए। कुछ मुद्दे जो वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में कई जगह बिखरे हुए थे उन्हें एक जगह रखकर ज्यादा सरल और स्पष्टता प्रदान करने की सफल कोशिश की गई है। अधिकांश बदलाव करदाता की सहुलियत के लिए किए गए हैं। पूर्व वर्ष जिसकी आय का निर्धारण अगले वर्ष, जिसे निर्धारण वर्ष कहा जाता है इन दो परिभाषाओं की जगह एक ही परिभाषा 'कर वर्ष' रखा गया है। तालिकाओं और सूत्रों के माध्यम से ज्यादा पठनीय और निश्चित बनाने की कोशिश हुई है। विभिन्न कर अपराधों के लिए सजा को कम किया गया है सश्रम कारावास की जगह सामान्य कारावास की व्यवस्था दी गई है। कई अपराधों के लिए केवल फाइन रखा गया है।

श्री गर्ग ने बताया कि नया आयकर अधिनियम, वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 से लगभग आधा है, सरल है, सहज है। लैटिन के शब्दों की जगह सामान्य अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल से नया कानून आम करदाता की समझ और अनुपालन बढ़ाएगा। इस सबके परिणामस्वरूप कराधार बढ़ेगा। इसमें करदाताओं द्वारा लंबे समय से दी जाने वाली कई सलाह को समाहित करने का प्रयास किया गया है जिससे करदाता स्वेच्छा से कर अनुपालन कर देश उन्नति में सहयोग दे सके। कार्यक्रम के दौरान वित्तीय बिल 2026 में प्रस्तावित बदलावों की भी विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में आयकर अधिकारी, हरदा श्री मनोज सोनवंशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकार, आम करदाता जैसे व्यापारी आदि और वाणिज्य विषय के छात्र-छात्राओं के साथ डिग्री कॉलेज के प्राध्यपकों ने भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की।

संचालक सैनिक कल्याण नर्मदापुरम एवं हरदा के भ्रमण पर

नर्मदापुरम (निप्र)। ब्रिगेडियर श्री अरुण नायर, सेना मेडल, संचालक सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल, 24 फरवरी 2026 को जिला नर्मदापुरम और 25 फरवरी 2026 को जिला हरदा के भ्रमण पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। 24 फरवरी को ब्रिगेडियर श्री नायर पिपरिया, इटारसी और नर्मदापुरम में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से भेंट करेंगे। इसके बाद, 25 फरवरी को वह हरदा जिले में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से मुलाकात करेंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर अनुराग सक्सेना ने जिले के समस्त पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से अनुरोध किया है कि वे तय दिनांक और स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

कलेक्टर ने जिला आबकारी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

अभिलेख व्यवस्था,व राजसात वाहनों के संदर्भ में निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने गुरुवार को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन कार्यप्रणाली, अभिलेख संधारण, राजसात वाहनों, उपकरणों तथा कर्मचारियों की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया कि मदिरा के अवैध परिवहन में जब्त कर राजसात किए गए वाहनों की नियमानुसार शीघ्र नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि शासन को राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने कार्यालयीन अभिलेखों को वर्षवार छांटकर बस्ता बनाकर रखने तथा प्रत्येक बस्ते में अभिलेखों की सूची संलग्न कर सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कार्यालयीन अलमारियों में रखे गए अभिलेखों एवं पंजियों की सूची तैयार कर अलमारी के बाहर चस्पा कराने के निर्देश दिए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर अभिलेखों को आसानी से खोजा जा सके। साथ ही पुराने एवं अनुपयोगी उपकरणों को नियमानुसार राइट ऑफ करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने समस्त शाखाओं की अलमारियों में रखे अभिलेखों की सूची बाहर प्रदर्शित करने तथा अलमारियों में सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर की जानकारी सहित नेम प्लेट लगाने हेतु ताकिद किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित किया, ताकि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और कार्यालयीन कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।इस दौरान संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर-एसपी द्वारा कुबेरेश्वर धाम का निरंतर निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। गत 14 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम में रूद्राक्ष महोत्सव के तहत शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। सभी व्यवस्थाएं एवं सेवायें सुचारू रूप संचालित हो रही है। कलेक्टर श्री बालागुरु के. एवं एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। इस क्रम में आज भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धाम परिसर में स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा यातायात संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए।

'मन की बात' देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक प्रभावी प्लेटफार्म : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री ने मन की बात से जनसामान्य को देश हित और सबके विकास के लिए प्रेरित किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'मन की बात' देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक प्रभावी प्लेटफार्म है। देश में मैदानी स्तर पर घटित होने वाली सूक्ष्मतम गतिविधियों का वे ध्यान रखते हैं और उन्हें देशवासियों से साझा करते हैं। किसानों द्वारा एक ही स्थान पर विविध फसलें लेने के लिए किया गया नवाचार हो या केरल में बच्चे के अंगदान का मामला हो मन की बात में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उल्लेख किए गए यह सब प्रसंग कई लोगों को प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा तमिलनाडु की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री जयललिता को याद करना देश की विविधता को अभिव्यक्ति देने के समान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों में समग्रता और सबके विकास की सोच प्रकट होती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इस संवाद में कभी राजनैतिक विषय नहीं आते, वे सदैव देश हित को ही प्राथमिकता देते हैं। उनका यह विजन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के श्रवण के बाद मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन स्थित स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों तथा स्थानीय रहवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, श्री राहुल कोठारी, श्री रविन्द्र यति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी अन्नदाता, युवा, महिला, गरीब सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश के कोने-कोने में विकास, जनकल्याण के लिए हो रहे नवाचारों और पहल का ध्यान रखना और उन्हें देशवासियों से नियमित तौर पर साझा करना सराहनीय है। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई एम्पैक्ट समिट-2026 के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समिट में प्रदेश के कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रही पहल को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के हित में एआई का किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है, इस पर विचार करना ही हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश उदार और उदात विचारों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेगा।

रायसेन-उज्जैन में प्रेमी जोड़े ने एक साथ सुसाइड किया

350 किमी दूर इंजीनियर बॉयफ्रेंड ने पहले हाथ, गले की नस काटी, करंट लगाया, नाकाम रहा तो फांसी लगाई

रायसेन (नप्र)। शनिवार को मध्य प्रदेश में आत्महत्या से जुड़ी दो खबरें सामने आईं। एक मामले में युवती ने रायसेन के उदयपुरा में फांसी लगाई। वहीं, दूसरा मामले यहां से 350 किलोमीटर दूर उज्जैन जिले के पवासा थाना क्षेत्र का है। यहां एक युवक ने भी ठीक उसी समय फांसी पर लटककर खुदकुशी कर ली।

जब दोनों घटनाएं हुईं तो किसी ने दूर-दूर तक भी नहीं सोचा था कि इनकी कड़ी एक ही निकलेगी। रविवार को पता चला कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे। मौत को गले लगाने से पहले दोनों ने एक-दूसरे को फोन किया था।

कॉल डिटेल्स खंगालने पर अफेयर का पता चला- उदयपुरा थाना प्रभारी जयवंत सिंह काकोडिया ने बताया कि साक्षी धाकड़ (23) चिल्ली गांव में अपने नाना के घर रह रही थी। यहीं उसने

सुबह 6 बजे सुसाइड किया। जबकि युवक ऋषभ मीणा (26) ने पहले हाथ और गले की नस काटी, फिर करंट लगाया। नाकाम रहा है तो कमरे के बाहर लगी रेलिंग पर फंदा फंसाकर लटक गया।

दोनों की रातभर हुई थी बातचीत- पवासा थाना प्रभारी गमर मण्डलोई ने बताया कि ऋषभ उज्जैन के मक्सी रोड स्थित केसरबाग कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। वह पेशे से इंजीनियर था और उज्जैन की ही एक कंस्ट्रक्टिंग कंपनी में साइट इंजीनियर के रूप में काम करता था। मूल रूप से रायसेन का ही रहने वाला था।

मोबाइल की कॉल डिटेल और चैट की शुरुआती जांच में दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंधों की पुष्टि हुई है। शुक्रवार रात भर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे ऋषभ ने साक्षी को आखिरी कॉल किया।

इसके बाद उसने अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दिया। पुलिस के अनुसार, दोनों गांवों के बीच भले ही करीब 350 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन आत्महत्या का समय और फैसला लगभग एक जैसा रहा।

जबलपुर विवाद में अब तक 5 एफआईआर, 61 उपद्रवी गिरफ्तार

48 घंटे बाद सिहोरा में हालत सामान्य, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, धरपकड़ जारी

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के सिहोरा में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान साउंड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नियंत्रण में है। दुकानें खुल चुकी हैं। आम जनजीवन सामान्य हो चुका है। गुरुवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं वार्ड नंबर 5 सहित संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय ने मौके पर पहुंचकर हालात की समीक्षा की।

सामने आई थीं, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर लगातार गिरफ्तारियां कर रही है।

200 से अधिक पुलिस बल तैनात- प्रशासन के अनुसार, पूरे मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कुल 61 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस दोनों पक्षों से मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। घटना वाली रात 49 गिरफ्तारियां हुई थीं। उसकी अगली रात 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विवाद के बाद एहतियातन 200 से अधिक पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी सिहोरा में तैनात हैं।

बाजार में चहल-पहल, हालात सामान्य- अधिकारियों के मुताबिक स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। शनिवार को बाजार और बस स्टैंड पर चहल-पहल लौटी। बोर्ड परीक्षार्थी पुलिस सुरक्षा में अपने-अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

एसपी संपत उपाध्याय ने कहा, अब सिहोरा में पूरी तरह शांति है। बाजार वगैरह खुल चुके है। सभी लोग सामान्य दिनों की तरह अपना काम कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर वहां पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों में 2 एडिशनल एसपी और 3 डीएसपी शामिल हैं।

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी ने 3 कमरों वाले कॉलेज को दे दी मान्यता, नियमों को ठेंगा, कैग ने खोली पोल

भोपाल (नप्र)। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू), भोपाल ने यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करते हुए, एक सरकारी कॉलेज को संबद्धता दे दी। यह कॉलेज रायसेन जिले के बाड़ी में एक सरकारी कन्या विद्यालय के तीन कमरों में चल रहा था, जबकि इसके पास यूजीसी के 2009 के नियमों के अनुसार आवश्यक भूमि, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं नहीं थीं। रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज केवल 420 वर्ग फुट में तीन कमरों में चल रहा था, फिर भी उसने 60 छात्रों को प्रवेश दिया।

क्या कहती है यूजीसी की गाइडलाइन- यह कॉलेज भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यूजीसी के नियमों के अनुसार, ग्रामीण कॉलेजों के लिए पांच एकड़ बिना विवाद की जमीन, साथ ही लेक्चर, सेमिनार, लैब और पुस्तकालय के लिए पर्याप्त भवन होना अनिवार्य है। इसके अलावा, पानी, बिजली, वेंटिलेशन, शौचालय, सीवर, 1,000 किताबों वाली लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम जैसी आवश्यक सुविधाएं भी जरूरी हैं।

यूनिवर्सिटी ने इग्नोर किए सभी नियम- विश्वविद्यालय ने इन सभी मानदंडों को नजरअंदाज कर दिया और कॉलेज को संबद्धता दे दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नियमों का सत्यापन किए बिना संबद्धता प्रदान की, जिससे ग्रामीण छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। विश्वविद्यालय ने सितंबर 2024 में अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के आदेशों और निरीक्षण समिति की मंजूरी का पालन किया था, लेकिन ऑडिटरों ने इसे खारिज कर दिया।

तीन अन्य कॉलेजों में मिली खामी- ऑडिट में कहा गया है कि तीन अन्य कॉलेजों को भी आवश्यक एनएएसी या समकक्ष मान्यता के बिना स्थायी संबद्धता मिली, जो शहरी क्षेत्रों में कम से कम दो एकड़ भूमि और वैधानिक मान्यता की मांग करने वाले नियमों का उल्लंघन था। ऑडिट ने विश्वविद्यालय के लगातार अनदेखी करने और उच्च शिक्षा में शासन और अनुपालन पर सवाल उठाए। क्क अधिकारियों ने कहा कि कॉलेज को नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है और अब वह सभी मानदंडों का पालन कर रहा है।

जवाहर लाल नेहरू कॉलेज में भी मिली अनियमितता

भोपाल के जवाहर लाल नेहरू कॉलेज में भी अनियमितताएं पाई गईं। यह कॉलेज 2,400 वर्ग फुट के प्लॉट पर किराए की इमारत में चल रहा था, जिसमें 9,600 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र था और खेल के मैदान की भी जगह नहीं थी। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय ने 2009-10 में इसे स्थायी संबद्धता दे दी। कॉलेज के पास NAAC या किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी से कोई मान्यता नहीं थी, फिर भी विश्वविद्यालय ने सालाना नवीनीकरण किया।

भोपाल के विकास पर कैग की रिपोर्ट

इसके अलावा, कैग की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भोपाल शहर के लिए पिछले 21 सालों से कोई विकास योजना नहीं है। 1975 से केवल दो भोपाल विकास योजनाएं स्वीकृत हुई हैं - 1991 और 2005 में। राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में भोपाल विकास योजना-2031 का मसौदा 36 महीने की देरी के बाद वापस कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल विकास योजना 2005 अभी भी लागू है। नतीजतन, भोपाल विकास योजना 2005 एक बेंचमार्क बनी हुई है, जो वर्तमान विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है।

यह है मामला

1. यूजीसी के 2009 के नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज के पास 5 एकड़ जमीन और लाइब्रेरी-लैब जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं, लेकिन बाड़ी कॉलेज के पास इनमें से कुछ भी नहीं था।
2. ऑडिट में पाया गया कि कॉलेज एक गर्ल्स स्कूल के अंदर सिर्फ 420 वर्ग फुट की जगह में चल रहा है, जहां 60 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है।
3. सिर्फ बाड़ी ही नहीं, भोपाल के जवाहर लाल नेहरू कॉलेज समेत चार अन्य कॉलेजों को भी बिना जरूरी जमीन और मान्यता के वर्षों से स्थायी संबद्धता दी जा रही है।
4. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि सरकार की घोषणा के बाद कॉलेज को 'जल्दबाजी' में शुरू किया गया था, हालांकि ऑडिटर्स ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
5. कैग ने चेतावनी दी है कि बुनियादी सुविधाओं के बिना दी गई इन मान्यताओं से ग्रामीण और गरीब छात्रों के सीखने के स्तर पर बेहद बुरा असर पड़ा है।

स्मार्ट मीटर से जबलपुर, भोपाल संभाग में 692 करोड़ का मुनाफा

विरोध और शिकायतों के बावजूद नरसिंहपुर में 57 प्रतिशत, भोपाल में 50 फीसदी स्मार्ट मीटर लगे

भोपाल (नप्र)। एमपी में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर आम जनता और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। भोपाल उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा में ऊर्जा मंत्री से स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल पूछे। दोनों संभागों की बिलिंग दक्षता में बड़ा सुधार हुआ है। जबलपुर संभाग में यहां बिलिंग एफिशिएंसी 73.77 प्रतिशत से बढ़कर 82.16 प्रतिशत हो गई है, जिससे राजस्व में 314 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

भोपाल संभाग में बिलिंग दक्षता 76.86 प्रतिशत से बढ़कर 81.57प्रतिशत पर पहुंच गई है,

जिससे राजस्व संग्रहण 378 करोड़ बढ़ा। कुल मिलाकर, स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली से सरकार को इन दो संभागों से 692 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

विधायक के सवाल पर ऊर्जा विभाग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि स्मार्ट मीटर के कारण अकेले भोपाल और जबलपुर दो संभागों में 692 करोड़ के राजस्व की बढ़ोत्तरी हुई है।

विधानसभा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की जानकारी के अनुसार, भोपाल और जबलपुर संभागों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद न केवल बिजली चोरी के मामलों में कमी आई है, बल्कि सरकारी खजाने में भी राजस्व बढ़ा है।कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के सवाल पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्मार्ट मीटर की जानकारी विधानसभा में दी।

बिजली विभाग की आमदनी बढ़ी- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, स्मार्ट मीटर लगने से

स्मार्ट मीटर लगाने की वर्तमान स्थिति- संभागवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, अब तक गैर-कृषि उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जबलपुर संभाग में कुल 26.55 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 50 प्रतिशत (7.86 लाख) मीटर लगाए जा चुके हैं। जबलपुर जिले में सबसे अधिक 45 प्रतिशत और नरसिंहपुर में 57 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। जबकि, भोपाल संभाग में कुल 16.84 लाख उपभोक्ताओं में से 30 प्रतिशत (5.09 लाख) स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

बंगाल चुनाव के बाद भाजपा सत्ता-संगठन में बदलाव

कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बाद देश के साथ भाजपा सत्ता और संगठन में फेरबदल होगा। चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में कुछ केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री भी नितिन की टीम में जा सकते हैं। तय माना जा रहा है कि नितिन की टीम में छत्तीसगढ़ से एक-दो नेता तो रहेंगे ही। राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम बनने के बाद राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं। कुछ मंत्रियों को ड्राप करने के साथ कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। खबर है कि बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले महीने हो जाएगी। अप्रैल में चुनाव निपट जाएगा। तब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी संपन्न हो जाएगा और राज्यसभा के चुनाव भी निपट जाएंगे। अप्रैल-मई में राज्य की विष्णुदेव साय सरकार का कार्यकाल भी करीब-करीब ढ़ाई साल हो जाएगा।

भरोसे के अफसर

2006 बैच के आईएएस अंकित आनंद को साय सरकार का काफी भरोसेमंद और रिजल्ट देने वाला अफसर माना जा रहा है। इसके चलते साय सरकार अंकित आनंद को नई -नई जिम्मेदारियां देते जा रही है। अंकित आनंद आवास और पर्यावरण विभाग, पंजीयन और आईटी विभाग के सचिव हैं। वे पर्यावरण मंडल और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। आईटी को छोड़कर अन्य विभागों के मंत्री ओपी चौधरी हैं। अब सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सीईओ भी बना दिया है। बताते हैं छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण साय सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की संरचना का प्रस्ताव है। एनसीआर में उत्तरप्रदेश,हरियाणा और राजस्थान के कई शहर शामिल हैं। सीआरडीए में राजधानी के आसपास के जिलों के कई शहर को शामिल किए जाने की खबर है। अब अंकित आनंद कई दायित्वों के साथ एनसीआर की तर्ज पर सीआरडीए को किस तरह अमलीजामा पहनाते हैं और सरकार के भरोसे पर कितने खरा उतरते हैं ,इसका लोगों को इंतजार है।

आखिर मिल गया पत्रकारिता विवि को कुलपति

लंबे इंतजार के बाद राज्य के पत्रकारिता विश्वविद्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय) को कुलपति मिल गया। कई महीनों से रायपुर कमिश्नर महादेव करे पत्रकारिता विश्वविद्यालय को चला रहे थे। हिसार (हरियाणा) के प्रोफ़ेसर मनोज दयाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय को चलाएंगे। प्रोफ़ेसर मनोज दयाल रिटायर्ड हैं,सो आर्डर निकलते ही अगले दिन सुबह-सुबह हिसार से रायपुर पदभार ग्रहण करने पहुंच गए। अब तक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति छत्तीसगढ़ के बाहर के ही बने हैं। चर्चा है कि एक छत्तीसगढ़िया भी कुलपति की दौड़ में था,पर समीकरण बैठा नहीं पाने के कारण चूक गया। अब प्रोफ़ेसर मनोज दयाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का किस तरह और कितना कायाकल्प कर पाते हैं, या फिर वानप्रस्थ काटकर चले जाते हैं ,यह तो समय बताएगा। बताते हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए कुल छह लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें तीन तो पहले राउंड में ही कट गए। तीन का पैनल बना। पैनल में ही कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया था। आखिर में दो ही दावेदार बचे, जिसमें प्रोफ़ेसर मनोज दयाल बाजी मार गए।

क्या अजय चंद्राकर को भेजा जाएगा राज्यसभा ?

प्रदेश में बड़ा हल्ला है कि पूर्व मंत्री और कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अजय चंद्राकर चार बार के विधायक हैं और डॉ रमन सिंह की सरकार में दो टर्म मंत्री रहे। साय मंत्रिमंडल में कुर्मी समाज से टंकराम वर्मा को मंत्री बनाए जाने से अजय चंद्राकर मंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए। कहते हैं विधानसभा के भीतर अजय चंद्राकर आक्रामक तेवर अपनाते हैं। कई मंत्री तो उनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं। चर्चा चल पड़ी है कि अजय चंद्राकर की रणनीति से साय सरकार के कुछ पावरफुल मंत्री और संगठन के कुछ नेता उनको दिल्ली भेजकर अपनी साख बचाने के फेर में हैं। लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट देकर जिस तरह बृजमोहन अग्रवाल को राज्य की राजनीति से दूर किया गया, वैसे ही अजय चंद्राकर को राज्यसभा में भेजकर प्रदेश की राजनीति से हटाने की बात राजनीतिक गलियारों में चल पड़ी है। प्रदेश के नेता या अजय चंद्राकर को न चाहने वाले कुछ भी शिगूफा छोड़ें, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा कौन जाएगा, इसका फैसला तो दिल्ली करेगा। पिछली दफे राज्यसभा के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम कैसे आया किसी को पता भी नहीं चल पाया। इस बार अप्रैल में छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही है। मार्च में चुनाव है। एक-एक सीटें भाजपा और कांग्रेस के खाते में आएंगी।

आईएएस बनने का रिकॉर्ड

यूपीएससी ने इस बार सात डिप्टी कलेक्टरों और एलाइड सेवा के दो अफसरों को आईएएस अवार्ड किया। इस बार की प्रमोटी आईएएस की सूची कई मायनों में महत्वपूर्ण है और चर्चित भी। बीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने नायब तहसीलदार से आईएएस बनने का रिकार्ड बना लिया। आमतौर पर नायब तहसीलदार पदोन्नत होकर डिप्टी कलेक्टर तक पहुँच पाते हैं। अनुकंपा नियुक्ति वाले डिप्टी कलेक्टर सौमिल रंजन चौबे भी आईएएस बन गए। सौमिल रंजन नक्सली हमले में शहीद आईपीएस विनोद कुमार चौबे के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सौमिल रंजन को डिप्टी कलेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी थी। डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने वाले सुमित अग्रवाल और संदीप अग्रवाल भाई हैं। पिछले साल आईएएस से चूके तीरथराज अग्रवाल को इस बार आईएएस मिल गया। तीरथराज अभी वन मंत्री केदार कश्यप के ओएसडी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ओएसडी आशीष टिकरहिया भी आईएएस बन गए हैं। वित्त सेवा के ऋषभ कुमार पाराशर और जीएसटी के अधिकारी तरुण कुमार किरण भी आईएएस बन गए। चर्चा है कि इस बार आईएएस बनने वाले दो अफसरों पर राज्य के एक सचिव स्तर के अधिकारी की बड़ी कृपा बरसी।

सवाल एसडीएम की साख का

प्रशासन में कलेक्टर के बाद एसडीएम की बड़ी भूमिका होती है, पर छत्तीसगढ़ में घटित कुछ घटनाओं ने एसडीएम पद की गरिमा को धूल-धूसरित कर दिया है। पिछले महीने गरियाबंद जिले के मैनपुर के एसडीएम अश्लील नृत्य देखने चले गए और अब बलरामपुर जिले के कुसमी के एसडीएम ने एक ग्रामीण को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। सरकार ने दोनों एसडीएम को निलंबित कर दिया है, पर बड़ा सवाल है कि पद की गरिमा का मान नहीं रख पाने वालों को क्या लोक सेवक रहना चाहिए। दोनों एसडीएम लोक सेवक ही हैं। लोक सेवकों तो संवेदनशील होना चाहिए। लगता है कि लोक सेवकों को अब ज्यादा प्रशिक्षण और उन्हें उनके कर्तव्य का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। दैहिक शोषण के आरोप में एक एक डिप्टी कलेक्टर के निलंबित होने की भी खबर आई है। ऐसी खबरों से निचले स्तर के प्रशासनिक सेवाओं पर जनता का भरोसा टूटते देर नहीं लगेगी। समय है सरकार सख्त हिदायत दे और उन्हें जबावदेह बनाए।

नेता प्रतिपक्ष के रुख पर नजर

विधानसभा का बजट सत्र 23 फ़रवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार बजट सत्र ज्यादा लंबा तो नहीं है, पर विपक्ष के लिए अवसर है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। धान खरीदी से लेकर किसान की पिटाई और अन्य घटनाओं को लेकर विपक्ष सदन में आक्रामक हो सकता है, पर सबकी नजर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत पर है। डॉ महंत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मध्यप्रदेश में मंत्री, केंद्र में मंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष के रुख से सदन का माहौल तय होता है। अब देखते हैं बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका किस तरह की रहती है और सदन का वातावरण कैसा रहता है।

आईएफएस अधिकारी बजाज अब जिंदल ग्रुप में

रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी एस एस बजाज अब जिंदल स्टील के रायपुर आफिस संभालेंगे। वे प्रदीप टंडन का स्थान लेंगे। प्रदीप टंडन 31 मार्च को जिंदल स्टील को अलविदा कह देंगे। प्रदीप टंडन काफी साल जिंदल स्टील एंड पावर में रहे। एस एस बजाज ने जिंदल स्टील ज्वॉइन कर लिया है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में श्री बजाज नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में वे एनआरडीए के सीईओ रहे। बजाज साहब छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के डीजी का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा सरकार के कई विभागों की जिम्मेदारी उनके पास रही है। श्री बजाज ने सरकार के बाद अब कारपोरेट में कदम रखा है।